

My Notes

राष्ट्रीय

कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स

नीति आयोग ने 13 जून 2018 को 'कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स' जारी की जिस पर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड सबसे निचले पायदान पर हैं। आयोग की इस इंडेक्स पर गैर-हिमालयी राज्यों में गुजरात पहले नंबर पर है जबकि बिहार, यूपी, हरियाणा और झारखंड सबसे निचले पायदान पर हैं। वहीं हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों की सूची में सबसे अच्छा प्रदर्शन त्रिपुरा का है।

क्या है

1. गुजरात पहले, मध्य प्रदेश दूसरे और आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर
2. नीति आयोग ने वर्ष 2016-17 के लिए इन राज्यों की रैंकिंग की है। आयोग की वाटर इंडेक्स पर सबसे ज्यादा स्कोर 76 गुजरात का है और रैंकिंग में यह पहले नंबर पर है जबकि झारखंड का स्कोर मात्र 35 और उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखंड का स्कोर सिर्फ 38 है।
3. इन राज्यों में झारखंड की रैंक 17वीं, हरियाणा की 16वीं, उत्तर प्रदेश की 15वीं और बिहार की 14वीं है।
4. 2015-16 में उत्तर प्रदेश की 14वीं रैंक थी। मध्य प्रदेश 69 स्कोर के साथ इस इंडेक्स पर दूसरे नंबर पर है।
5. आयोग का कहना है कि जिन राज्यों में जल का अभाव है, जल संसाधनों के प्रबंधन के मामले में उनका प्रदर्शन बेहतर है।
6. मसलन, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र का इस इंडेक्स पर उच्च स्थान है। आयोग ने उन राज्यों का भी उल्लेख किया है जिन्होंने जल प्रबंधन बेहतर करने की कोशिश भी की है।
7. राजस्थान ने इस मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। जहां तक हिमालयी और पूर्वोत्तर के राज्यों का सवाल है तो त्रिपुरा पहले नंबर पर जबकि हिमाचल प्रदेश दूसरे और उत्तराखंड छठे नंबर पर है।
8. आयोग का कहना है कि कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स पर जिन राज्यों का प्रदर्शन खराब है वहां देश की 50 प्रतिशत आबादी रहती है और खेती का केंद्र भी यही राज्य हैं।
9. ऐसे में इन प्रदेशों में जल प्रबंधन की खराब स्थिति आने वाले दिनों में संकट की ओर इशारा कर रही है। देश का 20 से 30 प्रतिशत कृषि उत्पादन इन्हीं राज्यों से होता है। ऐसे में जल संकट गहराने से खाद्य सुरक्षा पर भी खतरा होगा।

कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स पर राज्यों की रैंक रैंक गैर-हिमालयी राज्य

1. गुजरात
2. मध्य प्रदेश
3. आंध्र प्रदेश
4. कर्नाटक
5. महाराष्ट्र
6. पंजाब
7. तमिलनाडु
8. तेलंगाना
9. छत्तीसगढ़
10. राजस्थान
11. गोवा
12. केरल
13. उड़ीसा
14. बिहार
15. उत्तर प्रदेश
16. हरियाणा
17. झारखंड

रैंक हिमालयी व पूर्वोत्तर के राज्य

1. त्रिपुरा
2. हिमाचल प्रदेश
3. सिक्किम
4. असम
5. नागालैंड
6. उत्तराखंड
7. मेघालय

10. देश पर मंडराते जल संकट की ओर इशारा करते हुए आयोग की इस रिपोर्ट में कहा है कि भारत इस समय इतिहास के अब तक के सबसे खराब जल संकट का सामना कर रहा है और इसके चलते आजीविका पर भी खतरा मंडरा रहा है। लगभग 60 करोड़ भारतीयों को जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दो लाख लोगों की हर साल सुरक्षित पेयजल के अभाव में जान जा रही है।
11. 2030 तक देश में पेयजल की मांग दोगुनी हो जाएगी जिससे देश के जीडीपी की छह प्रतिशत तक हानि हो सकती है। यही वजह है कि जल के बेहतर प्रबंधन के इरादे से आयोग ने 'कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स' विकसित की है।

पूर्वोत्तर परिषद के पुनर्गठन को स्वीकृति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर परिषद के पुनर्गठन को स्वीकृति दे दी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर परिषद के पुनर्गठन में केंद्रीय गृहमंत्री को संस्था का पदेन अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किया गया था। इस संस्था में सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री सदस्य हैं। मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने की भी स्वीकृति दे दी है।

क्या है

1. एनईसी राज्य और केंद्र सरकार के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं को लागू करती है। नई व्यवस्था के अंतर्गत पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष गृह मंत्री होंगे और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होंगे तथा पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे। यह परिषद अंतर-राज्य विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श के लिए मंच प्रदान करेगी और भविष्य में अपनाये जाने वाले समान दृष्टिकोणों पर विचार भी करेगी।
2. एनईसी अब मादक द्रव्यों की तस्करी, हथियारों और गोला-बारूदों की तस्करी, सीमा विवादों जैसे अंतर-राज्य विषयों पर विचार-विमर्श के लिए विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों द्वारा किए जा रहे कार्यों को करेगी।
3. एनईसी के नए स्वरूप से यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कारगर संस्था बनेगी।
4. परिषद समय-समय पर परियोजना में शामिल परियोजनाओं/योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी, इन परियोजनाओं आदि के लिए राज्यों के बीच समन्वय के लिए कारगर उपायों की सिफारिश करेगी। परिषद को केंद्र सरकार द्वारा दी गई शक्तियां प्राप्त होंगी।

पृष्ठभूमि

1. एनईसी की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 के अंतर्गत की गई थी। इसकी स्थापना संतुलित और समन्वित विकास सुनिश्चित करने तथा राज्यों के साथ समन्वय में सहायता देने के लिए शीर्ष संस्था के रूप में की गई थी।
2. 2002 के संशोधन के बाद एनईसी को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय नियोजन संस्था के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है और एनईसी इस क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना बनाते समय दो या अधिक राज्यों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं और परियोजनाओं को प्राथमिकता देगी। परिषद् सिक्किम के मामले में विशेष परियोजनाएं और योजनाएं बनाएगी।

बांध सुरक्षा विधेयक, 2018 को स्वीकृति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बांध सुरक्षा विधेयक 2018 को संसद में प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। यह विधेयक राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को एकरूप बांध सुरक्षा प्रक्रियाओं को

अपनाने में मदद देगा, जिससे बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और इन बांधों से होने वाले लाभ सुरक्षित रहेंगे। इससे मानव जीवन, पशु धन और संपत्ति की सुरक्षा में भी मदद मिलेगी। अग्रणी भारतीय विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद प्रारूप विधेयक को अंतिम रूप दिया गया है।

क्या है

1. विधेयक में देश में निर्दिष्ट बांधों की उचित निगरानी, निरीक्षण, संचालन तथा रख-रखाव का प्रावधान है, ताकि उनका सुरक्षित काम-काज सुनिश्चित किया जा सके।
2. विधेयक में बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति गठित करने का प्रावधान है। यह समिति बांध सुरक्षा नीतियों को विकसित करेगी और आवश्यक नियमनों की सिफारिश करेगी।
3. विधेयक में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण का गठन नियामक संस्था के रूप में करने का प्रावधान है। यह प्राधिकरण नीति, दिशा-निर्देश और देश में बांध सुरक्षा के लिए मानकों को लागू करेगा।
4. विधेयक में राज्य सरकार द्वारा बांध सुरक्षा पर राज्य समिति गठित करने का प्रावधान है।

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण क्या है

1. यह प्राधिकरण बांध सुरक्षा संबंधी डाटा और व्यवहारों के मानकीकरण के लिए राज्य बांधसुरक्षा संगठनों और बांधों के मालिकों के साथ संपर्क बनाए रखेगा।
2. प्राधिकरण राज्यों तथा राज्य बांध सुरक्षा संगठनों को तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता उपलब्ध कराएगा।
3. प्राधिकरण देश के सभी बांधों का राष्ट्रीय स्तर पर डाटा बेस तथा प्रमुख बांध विफलताओं का रिकॉर्ड रखेगा।
4. प्राधिकरण किसी प्रमुख बांध की विफलताओं के कारणों की जांच करेगा।
5. प्राधिकरण नियमित निरीक्षण के लिए तथा बांधों की विस्तृत जांच के लिए मानक दिशा-निर्देशों और नियंत्रण सूचियों को प्रकाशित करेगा और अद्यतन रखेगा।
6. प्राधिकरण उन संगठनों की मान्यता या प्रत्ययन का रिकॉर्ड रखेगा, जिन्हें जांच, नए बांधों की डिजाइन और निर्माण का कार्य सौंपा जा सकता है।
7. प्राधिकरण दो राज्यों के राज्य बांध सुरक्षा संगठन के बीच या किसी राज्य बांध सुरक्षा संगठन और उस राज्य के बांध के स्वामी के बीच विवाद का उचित समाधान करेगा।
8. कुछ मामलों में जैसे, एक राज्य का बांध दूसरे राज्य के भू-भाग में आता है तो राष्ट्रीय प्राधिकरण राज्य बांध सुरक्षा संगठन की भूमिका भी निभाएगा और इस तरह अंतर-राज्य विवादों के संभावित कारणों को दूर करेगा।

बांध सुरक्षा पर राज्य समिति क्या है

1. यह समिति राज्य में निर्दिष्ट सभी बांधों की उचित निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रख-रखाव सुनिश्चित करेगी। समिति यह सुनिश्चित करेगी की बांध सुरक्षा के साथ काम कर रहे हैं।

पृष्ठभूमि

1. भारत में 5200 से अधिक बड़े बांध हैं और लगभग 450 बांध बनाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मझौले और छोटे हजारों बांध हैं।
2. भारत में बांध सुरक्षा के लिए कानूनी और संस्थागत व्यवस्था नहीं होने के कारण बांध सुरक्षा चिंता का विषय है। असुरक्षित बांध खतरनाक हैं और इनके टूटने से आपदा आ सकती है और परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान हो सकता है।
3. बांध सुरक्षा विधेयक, 2018 में बांधसुरक्षा संबंधी सभी विषयों को शामिल किया गया है। इसमें बांध का नियमित निरीक्षण, आपात कार्य योजना, विस्तृत सुरक्षा के लिए पर्याप्त मरम्मत और रख-रखाव कोष इंस्ट्रुमेंटेशन तथा सुरक्षा मैनुअल शामिल हैं। इसमें बांध सुरक्षा का दायित्व बांध के स्वामी पर है और विफलता के लिए दंड का प्रावधान है।

- इसमें प्रत्येक राज्य में राज्य बांध सुरक्षा संगठन स्थापित करने का प्रावधान है। यह संगठन फील्ड बांध सुरक्षा के अधिकारियों द्वारा चलाया जाएगा। अधिकारियों में प्राथमिक रूप से बांध डिजाइन, हाईड्रो मेकेनिकल इंजीनियरिंग, हाईड्रोलॉजी, भू तकनीकी जांच और बांध पुनर्वास क्षेत्र के अधिकारी होंगे।

मार्क-3 जारी रखने को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पोलर सेटेलाइट प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) जारी रखने के कार्यक्रम (छठें चरण) और इस कार्यक्रम के अंतर्गत 30 पीएसएलवी परिचालन प्रक्षेपण को वित्तीय सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी है। यह कार्यक्रम पृथ्वी अवलोकन, दिशा सूचक और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए सेटेलाइट के प्रक्षेपण की आवश्यकता को भी पूरा करेगा। इससे भारतीय उद्योग में उत्पादन भी जारी रहेगा। कुल 6,131 करोड़ रुपये के कोष की आवश्यकता है और इसमें 30 पीएसएलवी यान, आवश्यक सुविधा बढ़ाने, कार्यक्रम प्रबंधन और प्रक्षेपण अभियान की लागत शामिल है।

प्रमुख प्रभाव

- पीएसएलवी के परिचालन से देश पृथ्वी अवलोकन, आपदा प्रबंधन, दिशा सूचक और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए सेटेलाइट प्रक्षेपण क्षमता में आत्मनिर्भर बना है। पीएसएलवी जारी रखने के कार्यक्रम से राष्ट्रीय जरूरतों के अधिक सेटेलाइट प्रक्षेपण में क्षमता और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
- पीएसएलवी जारी रखने के कार्यक्रम के छठें चरण के दौरान अधिकतम भारतीय उद्योग की भागीदारी से प्रतिवर्ष आठ प्रक्षेपण करने की सेटेलाइट प्रक्षेपण की मांग पूरी होगी। 2019-2024 की अवधि के दौरान सभी परिचालन अभियान संपन्न हो जाएंगे।
- इस कार्यक्रम से पृथ्वी अवलोकन, दिशा सूचक और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए सेटेलाइट प्रक्षेपण की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा। इससे भारतीय उद्योग में उत्पादन भी जारी रहेगा।
- पीएसएलवी जारी रखने का कार्यक्रम 2008 में शुरू किया गया था और इसके चार चरण पूरे हो चुके हैं तथा 2019-20 के पहले छह माह तक पांचवें चरण के संपन्न होने की आशा है। छठें चरण की मंजूरी से 2019-20 से 2023-24 के पहले तीन माह के दौरान सेटेलाइट प्रक्षेपण अभियान में मदद मिलेगी।

फलैशबैक

- पीएसएलवी सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट (एसएसपीओ), जीओ सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (जीटीओ) और लो अर्थ ऑर्बिट (एलईओ) प्रक्षेपण अभियान में बहुपयोगी प्रक्षेपणयान के रूप में उभरा है।
- हाल ही में 12 अप्रैल 2018 को पीएसएलवी-सी41 के सफल प्रक्षेपण के साथ ही पीएसएलवी ने तीन विकास और 43 परिचालन प्रक्षेपण संपन्न किए हैं तथा पिछले 41 प्रक्षेपण भी सफल रहे हैं।
- पीएसएलवी ने अपनी उत्पादन क्षमता से स्वयं को राष्ट्रीय सेटेलाइट के लिए कार्य-यान के तौर पर स्थापित किया है, जिससे व्यावसायिक प्रक्षेपण के अवसरों पर तेजी से कार्य किया जा सकेगा।

लिम्फेटिक फाइलेरिया पर वैश्विक बैठक

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा ने लिम्फेटिक फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए आयोजित वैश्विक गठबंधन की 10वीं बैठक (जीईएलएफ) का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन संबोधन में श्री नड्डा ने कहा कि भारत लिम्फेटिक फाइलेरिया के संचरण और इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि

भावी पीढियां इस बीमारी से मुक्त रहें। भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरिया को समाप्त करने के प्रयासों तथा इस संदर्भ में किये जाने वाले शोध का हमेशा से स्वागत किया है।

क्या है

1. कार्यक्रम में श्री नड्डा ने 11 देशों को जीएईएलएफ पुरस्कार प्रदान किया। ये देश हैं- कंबोडिया, कुक द्वीप समूह, मित्र, मालदीव, मार्शल द्वीप समूह, न्यू, श्रीलंका, थाईलैंड, टोगो, टोंगा और वानुअतु। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भारत के लिए लिम्फेटिक फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए एक त्वरित योजना जारी की।
2. श्री नड्डा ने कहा कि लिम्फेटिक फाइलेरिया को समाप्त करने की दिशा में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों व विकास संगठनों के सम्मिलित प्रयास से सर्वाधिक प्रभावित 256 जिलों में से 100

फलैशबैक

1. लिम्फेटिक फाइलेरिया को आमतौर पर हाथी पांव के नाम से जाना जाता है भारत सहित 73 देश इस बीमारी की चपेट में हैं।
2. यह रोग क्युलैक्स मच्छर द्वारा फैलता है। यह मच्छर स्थिर गंदे पानी में तेजी से बढ़ता है।
3. जीएईएलएफ 72 देशों के राष्ट्रीय लिम्फेटिक फाइलेरिया मुक्ति कार्यक्रम का गठबंधन है। इससे एनजीओ, निजी क्षेत्र, अकादमिक और शोध संस्थान भी जुड़े हुए हैं।
4. बैठक 2 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। 2002 में दूसरी बैठक का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था।
5. अभी भारत 10वीं बैठक की मेजबानी कर रहा है।

जिलों ने उन्मूलन लक्ष्य हासिल कर लिया है। संचरण मूल्यांकन सर्वे (टीएस) द्वारा सत्यापन के बाद इन जिलों में बड़े पैमाने पर दी जाने वाली दवा कार्यक्रम को रोक दिया गया है। अभी ये जिले निगरानी में हैं।

3. लिम्फेटिक फाइलेरिया को समाप्त करने की रणनीति दो तथ्यों पर आधारित है। (1) वर्ष में एक बार बड़े पैमाने पर दवा कार्यक्रम ताकि कोई नया मामला सामने न आये। (2) रोगग्रस्त व्यक्ति की रूग्णता प्रबंधन के साथ बेहतर देखभाल।

नालंदा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2013 को वापस लेने के प्रस्ताव

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य सभा में लंबित नालंदा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना अक्टूबर, 2009 में थाईलैंड में आयोजित चौथी पूर्व एशिया शिखर बैठक में जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्य के आधार पर की गई थी। प्रेस वक्तव्य में एक गैर सरकारी, अलाभकारी, धर्मनिरपेक्ष और स्वशासी अंतरराष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने को समर्थन दिया गया था। इसके बाद संसद द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 पारित किया गया और यह 25 नवंबर, 2019 से प्रभावी हुआ।

क्या है

1. वर्तमान प्रस्ताव राज्य सभा में नालंदा विश्वविद्यालय (संशोधन), 2013 को वापस लेने से संबंधित है। 26 अगस्त, 2013 को राज्य विधेयक सभा में प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 के कुछ प्रावधानों में संशोधन करना और कुछ नए प्रावधान जोड़ना था।
2. नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 के अनुच्छेद 7 के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के गवर्निंग बोर्ड का गठन कर लिया गया है और यह भारत के माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति से 21.11.2016 से प्रभावी है।
3. प्रस्तावित संशोधनों पर आगे बढ़ने के लिए कोई अंतिम निर्णय लेने से पहले नालंदा विश्वविद्यालय के गवर्निंग बोर्ड के साथ संशोधन विधेयक पर विचार-विमर्श की आवश्यकता होगी।

4. वर्तमान गवर्निंग बोर्ड संपूर्ण नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 पर नए सिरे से भी विचार कर सकता है और जहां कहीं भी आवश्यक हो संशोधनों/जोड़ों का सुझाव दे सकता है।
5. सितंबर, 2014 में विदेश मंत्री श्रीमती सुष्मा स्वराज द्वारा विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य का शुभारंभ किया गया था। भारत के माननीय राष्ट्रपति विश्वविद्यालय के विजिटर हैं।
6. डॉ. विजय भटकर विश्वविद्यालय के चांसलर और प्रोफेसर सुनैना सिंह कुलपति हैं।
7. अभी विश्वविद्यालय के तीन अध्ययन केंद्रों-स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज, स्कूल ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्टडीज और स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज - में 116 विद्यार्थी हैं।
8. इनमें 21 देशों के 35 अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी शामिल हैं।

अग्नि-5 का हुआ सफल परीक्षण

भारत ने 3 जून 2018 को इंटर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 का सफल परीक्षण किया। ओडिशा के अब्दुल कलाम आइलैंड के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (आईटीआर) से इसका परीक्षण किया गया। यह आइलैंड ओडिशा के बालासोर जिले में मौजूद है। इस आइलैंड को व्हीलर आइलैंड भी कहा जाता है। यह छठवीं बार है जब मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण लॉन्च पैड नंबर 4 से सुबह के 9.48 मिनट पर किया गया।

क्या है

1. इसका आखिरी बार सफल परीक्षण इसी साल 18 जनवरी को किया गया था। अग्नि-5 मिसाइलों को डीआरडीओ ने विकसित किया है और अग्नि सीरीज की मिसाइलों को चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखकर जमीन पर मार करने लिए तैयार किया गया है।
2. अग्नि-5 मिसाइल की ऊंचाई करीब 17 मीटर और व्यास 2 मीटर है। 50 टन की यह मिसाइल डेढ़ टन तक परमाणु हथियार ढोने में सक्षम है। यह ध्वनि की गति से 24 गुना ज्यादा तेजी से जा सकती है।
3. इस मिसाइल के साथ ही भारत 5,000 से 55,000 किलोमीटर की दूरी तक वार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस देशों के ग्रुप में शामिल हो जाएगा। अभी यह क्षमता अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के ही पास है।
4. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा स्वदेश निर्मित यह परमाणु क्षमता वाली सरफेस-टू-सरफेस मिसाइल 5,000 से 8,000 किलोमीटर तक के दायरे में निशाना साध सकती है। यह चीन के लगभग हर हिस्से में पहुंच सकती है।
5. अग्नि-5 मिसाइल का वजन 50 टन है। इसकी मिसाइल की लंबाई 17 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है। यह अपने साथ एक टन से ज्यादा के परमाणु हथियार ले जा सकती है।
6. अग्नि-5 का आखिरी बार दिसंबर 2016 में परीक्षण किया गया था जिसे यह कहकर परिभाषित किया गया था कि यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) का आखिरी परीक्षण है।
7. अग्नि-5, अग्नि सीरीज की मिसाइलें हैं जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। आपको बता दें कि भारत के पास पहले से ही अग्नि-1, अग्नि-2 और अग्नि-3 मिसाइलें हैं।
8. इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ बनाई गई रणनीति के तहत तैयार किया गया है। वहीं अग्नि-4 और अग्नि-5 को चीन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

कब-कब हुआ अग्नि का परीक्षण

1. अग्नि-5 का पहला परीक्षण 19 अप्रैल, 2012 को किया गया था।
2. दूसरी बार सितंबर 15, 2013 को किया गया था।
3. तीसरी बार 31 जनवरी 2015 को इसका परीक्षण किया गया था।
4. चौथी बार 26 दिसंबर 2016 को इसका परीक्षण हुआ।

आयुष उद्यमों के विकास के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए

एमएसएमई मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ने 4 जून 2018 को नई दिल्ली में आयुष और एमएसएमई मंत्रियों की उपस्थिति में एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह एमओयू देश में आयुष उद्यमों के विकास के लिए दोनों मंत्रालयों के संस्थानों और योजनाओं के जरिए सामंजस्य सुनिश्चित करेगा। इस साझेदारी का उद्देश्य 'समग्र स्वास्थ्य सेवा' में भारत को एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है।

क्या है

1. आयुष तेजी से बढ़ता क्षेत्र है, जिसमें निवारक, उपचारात्मक और पुनर्वास स्वास्थ्य के लिए असीम संभावनाएं हैं और यह भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा रहा है।
2. आयुष उद्योग में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी दवा निर्माण इकाइयों के साथ-साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के स्वास्थ्य सेवा डिलीवरी केंद्र शामिल हैं और इनमें मुख्यतः एमएसएमई का प्रभुत्व है, जिन्हें विकास के साथ-साथ आयुष की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए उद्यमिता विकास, क्षमता निर्माण और वित्तीय सहायता के क्षेत्र में मार्गदर्शन की आवश्यकता है।
3. आयुष क्षेत्र का घरेलू बाजार पिछले दशक के दौरान सतत रूप से आगे बढ़ा है। इसके अलावा, विश्व भर में पारंपरिक दवाओं की स्वीकार्यता भी सुनिश्चित हुई है।
4. अतः आयुष उत्पादों जैसे कि पूरक खाद्य पदार्थों, पौष्टिक-औषधीय पदार्थों और हर्बल अर्क के निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे लाभान्वित होने के लिए एमएसएमई और आयुष मंत्रालय इस क्षेत्र में उद्यमों को विकसित करने के लिए आपस में हाथ मिलाने पर सहमत हो गए हैं।
5. दोनों मंत्रालय आयुष क्षेत्र में उद्यमिता के विकास के लिए क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित करेंगे और एमएसएमई मंत्रालय सिडबी से लाभों की प्राप्ति हेतु आयुष उद्योगों के लिए नई योजनाएं तैयार करेगा।

पेरिस अधिनियम (1971) से संबंधित भारत गणराज्य की सरकार की घोषणा

28 मार्च, 2018 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने एक घोषणा अधिसूचित की, जिसमें 7 अक्टूबर, 1974 की भारत गणराज्य की सरकार की धरोहर का उल्लेख करते हुए 9 सितम्बर, 1886 की साहित्यिक एवं कलात्मक लेखन पर लेखन संबंधी बर्न सम्मेलन के अनुमोदन के साधन, जो 24 जुलाई, 1971 को पेरिस में संशोधित किए गए थे (बर्न अधिसूचना संख्या-59 देखें) तथा इसके तत्पश्चात धरोहर दिनांक 01 फरवरी, 1984 तथा 7 जून 1984 की घोषणाएं जिनके अनुसार भारत गणराज्य की सरकार 10 साल की अवधि, जो 10 अक्टूबर, 2024 को समाप्त होगी, तक बर्न सम्मेलन के परिशिष्ट के अनुच्छेद 2 तथा 3 के तहत प्रदत्त विशेषाधिकार का उपभोग (क्रमशः बर्न सम्मेलन संख्या 108 तथा 110) कर सकेगी। उक्त घोषणा भारत गणराज्य के क्षेत्र के संबंध में 28 मार्च, 2018 को लागू होगी।

क्या है

1. परिशिष्ट के अनुच्छेद 2 से भारत गणराज्य को ऐसे ग्रंथ के अनुवाद का विशेषाधिकार जिसका प्रकाशन पुनः छपाई या समरूप फार्म में पुनर्लेखन के रूप में हुआ है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा केवल शिक्षण, छात्रवृत्ति अथवा अनुसंधान के उद्देश्य से प्रदान किया गया है।
2. परिशिष्ट के अनुच्छेद 3 से भारत गणराज्य को ऐसे ग्रंथों, जिनका प्रकाशन पुनः छपाई या समरूप फार्म में पुनर्लेखन के रूप में हुआ है अथवा कानून के तहत तैयार की गई श्रव्य-दृश्य फिक्सेशन के श्रव्य-दृश्य रूप में हुआ है, की पुनः प्रस्तुति के विशेषाधिकार की एवज में ऐसा संस्करण प्रकाशित करने की अनुमति होगी जिसका 6 महीने की अवधि के दौरान वितरण/विक्रय न हुआ हो, इसमें अपवाद मात्र यह है कि इसके अनुवाद

का प्रकाशन स्वामी द्वारा अनुवाद के अधिकार या उसके प्राधिकार से न किया गया हो अथवा उसका अनुवाद भारत में सामान्यतः प्रयुक्त भाषा में न हुआ हो।

3. भारत 28 अप्रैल, 2018 से बर्न सम्मेलन का सदस्य रहा है और समय-समय पर परिशिष्ट के अनुच्छेद 2 तथा 3 के अनुसार घोषणाएं प्रस्तुत करता रहा है। प्रस्तुत या मौजूदा अधिसूचना भारत की पूर्व स्थिति के क्रम में ही है।

‘स्पाइक’ मिसाइल खरीदने के लिए भारत फिर बढ़ा आगे

इजरायल में बनी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्पाइक की खरीद के लिए भारत ने एक बार फिर से कदम बढ़ाए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दौरे से ठीक पहले नवंबर 2017 में भारत ने 50 करोड़ डॉलर (करीब 3,400 करोड़ रुपये) के इस मिसाइल सौदे को रद्द कर दिया था। इससे दोनों देशों के रक्षा संबंधों को झटका लगा था। बाद में जनवरी में नेतन्याहू के दौरे में उन्हें सौदे पर पुनर्विचार का आश्वासन दिया गया था।

क्या है

1. यह उन्नत मिसाइल इजरायल की सरकारी क्षेत्र की कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स बनाती है। अब इस सौदे में किसी बिचौलिये को न रखने की योजना है। अब यह सौदा दोनों देशों की सरकारों के बीच होगा। सौदे को रद्द करते समय कहा गया था कि रक्षा उपकरणों को विकसित करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय संस्था रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) इसी तरह की एंटी टैंक मिसाइल बना रही है। इसके शुरुआती परीक्षण सफल रहे हैं और कुछ वर्षों में स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल भारतीय सेना को मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हाल के महीनों में इस प्रक्रिया में कुछ बाधा आई।
2. अचूक निशाना लगाने के लिए प्रसिद्ध इजरायल की यह मिसाइल दुनिया में अपनी तरह की सबसे अच्छी मिसाइल मानी जाती है।
3. स्पाइक मिसाइल बनाने वाली कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स ने भारत सरकार की इस नई पहल पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।

स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल की खासियत?

1. स्पाइक एक मानव पोर्टेबल मिसाइल है। जिसका मतलब है कि इसे लॉन्चर और आदमी दोनों की मदद से दागा जा सकता है।
2. इस मिसाइल की दूसरी खासियत है इसकी मारक क्षमता। इस मिसाइल से 3-4 किलोमीटर की दूरी से हमला किया जा सकता है।
3. इसका मतलब ये हुआ कि दागने वाला सैनिक भी इस मिसाइल के साथ सुरक्षित रह सकता है।
4. ये मिसाइल मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में बॉर्डर पर तैनात सैनिकों के लिए ज्यादा कारगर साबित होती हैं।

‘सूर्य किरण-13’

आपसी सैन्य समन्वय स्थापित करने के लिए भारत-नेपाल संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास-सूर्य किरण-13 का अंतिम चरण प्रारंभ हो गया है। इस चरण में दोनों देशों की संयुक्त सेनाएं 72 घंटे आतंकवाद से निपटने की रणनीति और कौशल को साझा करेंगी। इसका मकसद अति दुर्गम और ऊंची पहाड़ियों में भी आतंकी गतिविधियों को मुंहतोड़ जवाब देना है।

क्या है

1. भारत-नेपाल संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास-सूर्य किरण 13 का आयोजन 30 मई से 12 जून तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में लगभग 300 भारतीय एवं नेपाली सैनिक भाग ले रहे हैं। इस दौरान

दोनों देशों की सेनाएँ विभिन्न काउन्टर इंसर्जेंसी एवं आतंकवाद विरोधी अभियानों के अनुरूप अपने-अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं।

2. इस सैन्य युद्धाभ्यास का मुख्य मकसद नेपाल तथा भारतीय सैनिकों में आपसी सैन्य समन्वय स्थापित करने के साथ-साथ दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियानों में सफल संचालन के लिए दोनों देशों की सेना के बीच समन्वय विकास स्थापित करना है। सैनिकों की संख्या के लिहाज से नेपाल के साथ आयोजित होने वाला सूर्य किरण युद्धाभ्यास सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है।
3. सूर्य किरण एक छमाही सैन्य संयुक्त युद्धाभ्यास है जो बारी-बारी से भारत एवं नेपाल में आयोजित किया जाता है। इस सैन्य युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य नेपाल तथा भारतीय सैनिकों में आपसी सैन्य समन्वय स्थापित करने के साथ-साथ दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियानों में सफल संचालन के लिए दोनों देशों की सेना के बीच समन्वय विकास स्थापित करना है।

संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास की खूबियां

1. इस सैन्य युद्धाभ्यास में आपदा प्रबंधन सहित राहत एवं बचाव के महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर दिया जाता है।
2. संयुक्त अभ्यास से दोनों देशों के बीच रक्षा समन्वय के साथ-साथ द्विपक्षीय संबंधों को बनाने में भी मदद मिलती है।
3. सूर्य किरण सैन्य अभ्यास साल में दो बार होता है, जो कि क्रमबद्ध रूप से दोनों ही देशों में आयोजित होता है। पिछले साल ही नेपाल के पश्चिमी जिला रूपनडेही में भारत और नेपाल का संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था।
4. सैनिकों की भागीदारी के लिहाज से सूर्य किरण सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है।
5. आपदा प्रबंधन और संयुक्त आपदा राहत अभियान भी इस अभ्यास का हिस्सा रहा हैं।
6. संयुक्त अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं को अनुभव, समझ और कौशल के आदान-प्रदान का प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा।
7. सैन्य अभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं एक-दूसरे के हथियारों, उपकरणों, रणनीति, तकनीक, पर्वतीय इलाके में आतंकवाद विरोधी माहौल में काम करने की प्रक्रियाओं से परिचित होंगे।
8. अभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच मेलजोल को और मजबूत करने के लिए खेलों का आयोजन भी किया जाता है। इसमें फुटबाल, बास्केटबाल, वॉलीबाल प्रतियोगिताएं भी कराई जाती हैं।

धनुष तोप जल्द सेना में होगी शामिल

गन कैरिज फैक्टरी जबलपुर में निर्मित धनुष तोप अपने अंतिम ट्रायल में सफल रही। सफल परीक्षण के बाद लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली पहली भारतीय तोप को भारतीय सेना में शामिल करने का रास्ता भी साफ हो गया है। गन कैरिज फैक्टरी जबलपुर के वरिष्ठ महाप्रबंधक एस. के. सिंह ने संवाददाताओं को बताया, धनुष ऑर्टिलरी गन अपने अंतिम ट्रायल में सफल रही। उन्होंने कहा, पोखरण में 2 जून से 7 जून के बीच हुए यूजर ट्रायल में 155 एमएम 45 केलीबर की 6 धनुष ऑर्टिलरी गन द्वारा सफलतापूर्वक फायरिंग की गई।

क्या है

1. अंतिम चरण के परीक्षण में पहले पांच दिनों में (2 जून से 6 जून तक) प्रत्येक गन से 50 फायर किए गए। इस प्रकार कुल 300 फायर किए गए। अंतिम दिन (7 जून को) सभी 6 तोपों से एक साथ एक लक्ष्य पर 101 फायर किए गए।

2. इसी बीच, इस फैक्टरी के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गन कैरिज फैक्टरी जबलपुर में निर्मित 155 एमएम की एक धनुष तोप की लागत करीब 14.50 करोड़ रुपये है, जबकि इस तोप के एक गोले की कीमत करीब एक लाख रुपये है।
3. उन्होंने कहा कि इसकी मारक क्षमता विदेश से आयातित उस बोफोर्स तोप से 11 किलोमीटर ज्यादा है, जिसे सेना ने कारगिल युद्ध में उपयोग किया था।
4. धनुष तोप का शीतकालीन परीक्षण सिक्किम व लेह में, ग्रीष्मकालीन ट्रायल पीएक्सई बालेश्वर, बवीना रेंज झांसी व पोखरण में सफलतापूर्वक किया गया।

देश का पहला सरकारी स्कूल ने रचा इतिहास

प्रदूषण मुक्त बिजली बनाने की दिशा में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के बाल वैज्ञानिकों ने नया इतिहास रच दिया है। हाँकर और इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में पार्ट टाइम जॉब कर अपनी पढ़ाई करने वाले चार छात्रों ने जिम से बिजली बनाने का आविष्कार किया है। उनके इस आविष्कार को नीति आयोग ने देश के टॉप फाइव आविष्कारों में पहले नंबर पर रखा है। आयोग ने आइआइटी दिल्ली व डेल कंपनी को तीन महीने के भीतर प्रोडक्ट के रूप में बाजार में लाने के निर्देश दिए हैं।

क्या है

1. नीति आयोग के टॉप फाइव आविष्कारों में पहले नंबर पर जगह बनाने वाले आविष्कार ईको जिम से बिजली बनाने वाले छात्रों का संघर्ष भी कम रोचक नहीं है।
2. पढ़ाई और इनवेंशन के प्रति जुनून कहें या फिर कुछ कर गुजरने की इच्छा, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले इन चार छात्रों ने कमाल कर दिखाया।
3. गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं में गणित विषय लेकर ये चारों छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर होने पर पढ़ाई और घर का खर्च चलाने के लिए इनको खुद काम करना पड़ता है। साथ मिलकर चारों छात्रों ने बिना कोयले और पानी के बिजली पैदा कर चमत्कार कर दिया है।
4. बीते दिनों नीति आयोग ने देशभर से नए आविष्कारों के संबंध में प्रोजेक्ट मंगाए थे, जिसमें 35 हजार स्कूलों ने आवेदन किया था। इनमें से आयोग ने देशभर से 30 प्रोजेक्ट का चयन किया था।
5. इसमें गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर के ईको जिम से बिजली बनाने वाले प्रोजेक्ट को भी शामिल किया गया था। टॉप 30 मॉडल की सूची बनाते वक्त आयोग ने इसे टॉप पांच में जगह दी थी। अब आयोग ने इसे नंबर वन प्रोजेक्ट का दर्जा दिया है।
6. टॉप 30 प्रोजेक्ट का दिल्ली स्थित आइआइटी में प्रजेंटेशन रखा गया था। आइआइटी दिल्ली के ऑटोमेशन के विभागाध्यक्ष सुनील कुमार झा समेत 15 चुनिंदा वैज्ञानिकों के सामने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने अपने आविष्कार के संबंध में जानकारी दी। ईको जिम से बिजली बनाने के लिए नीति आयोग ने अब बड़े पैमाने पर काम करना शुरू कर दिया है।
7. आयोग ने आइआइटी दिल्ली, डेल व एलएलएफ कंपनी को बतौर एजेंसी काम सौंप दिया है। तीन महीने के भीतर देश में बिजली का एक नया प्रोडक्ट सामने आएगा। इसे फ्यूचर एनर्जी का नाम दिया गया है।
8. बिलासपुर के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य डॉ. राघवेंद्र गौराहा के मुताबिक टॉप 30 प्रोजेक्ट में ईको जिम से बिजली उत्पादन को टॉप फाइव में जगह मिली है।
9. हमारे आविष्कार को नीति आयोग व आइआइटी दिल्ली के विभागाध्यक्ष सहित 15 वैज्ञानिकों ने जमकर सराहा है। आयोग ने इसे फ्यूचर एनर्जी का नाम दिया है।

केंद्र ने लागू किया प्रमोशन में आरक्षण

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर केंद्र सरकार ने अपने सभी विभागों व राज्य सरकारों को एससी-एसटी के लिए प्रमोशन में आरक्षण लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने मंत्रालयों, विभागों को कहा है कि सर्वोच्च अदालत के फैसलों के अनुरूप प्रोन्नति की अनुमति मंत्रालयों व विभागों को दे दी है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मद्देनजर विभागों में लंबित प्रमोशन के लिए कदम उठाएं। गौरतलब है कि पांच जून को सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विभागों में प्रमोशन के मामले पर सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया था कि सरकार कानूनी तरीके से प्रमोशन करने के लिए स्वतंत्र है। इस पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। हालांकि अदालत ने इसे अपने अगले आदेश पर निर्भर बताया था।

क्या है

1. गौरतलब है कि कई न्यायिक फैसलों के चलते प्रमोशन में आरक्षण को लेकर रोक लग गई थी। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया था कि प्रमोशन में आरक्षण को लेकर जितनी भी याचिकाएं और केंद्र सरकार की विशेष अनुमति याचिका लंबित हैं, उनका प्रमोशन नीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
2. ये प्रमोशन रिजर्वेशन कैटेगरी के पदों पर आरक्षण, जनरल कैटेगरी वाले पदों पर जनरल, मेरिट वाले पदों पर मेरिट के आधार पर होते रहेंगे।
3. नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर विभिन्न हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण कार्मिक विभाग (डीओपीटी) ने 30 सितंबर 2016 को एक आदेश निकालकर सभी तरह की पदोन्नति पर रोक लगा दी थी, तब से प्रमोशन को लेकर परेशान कर्मचारी इधर से उधर भटक रहे हैं। अब कार्मिक विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कानूनी राय लेने के बाद नए निर्देश जारी किए हैं।
4. कार्मिक विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रोन्नति के जो भी आदेश जारी किए जाएं उनमें इस बात का भी उल्लेख किया जाए कि प्रोन्नति सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश पर निर्भर करेगी। दरअसल, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है जिस पर संविधान पीठ का फैसला आना है।

अन्तरराष्ट्रीय

भारत ने OBOR पर चीन को अकेले दिया झटका

आठ देशों के शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) में भारत अकेला देश रहा जिसने चीन की महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड (OBOR) परियोजना का समर्थन नहीं किया। चीन ने इस परियोजना के लिए करीब 80 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से समझौता कर रखा है। एससीओ के दो दिवसीय सम्मेलन की समाप्ति पर जारी घोषणापत्र में कहा गया है कि रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, किर्गिजस्तान और तजाकिस्तान ने चीन के बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव (BRI) को अपने समर्थन की पुष्टि की है।

क्या है

1. घोषणापत्र में कहा गया कि सदस्य देशों ने यूरोशियन इकनॉमिक यूनियन के विकास समेत बीआरआई के क्रियान्वयन की दिशा में किए गए संयुक्त प्रयासों के लिए प्रसन्नता व्यक्त की है।
2. इसके अलावा एससीओ के स्पेस में एक व्यापक, खुला, पारस्परिक रूप से लाभकारी और समान साझेदारी को विकसित करने के लिए क्षेत्रीय देशों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय संघों की क्षमता के इस्तेमाल की भी बात कही गई।
3. चीन की 'एक क्षेत्र एक सड़क' (ओबीओआर) परियोजना पर एक परोक्ष टिप्पणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी बड़ी संपर्क सुविधा परियोजना में सदस्य देशों की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए।

4. उल्लेखनीय है कि भारत ओबीओआर का लगातार कड़ा विरोध करता रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के इस महत्वाकांक्षी प्रॉजेक्ट का एक हिस्सा, 50 अरब डॉलर का चीन-पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है।
5. भारत ने कहा है कि वह किसी ऐसे प्रॉजेक्ट को स्वीकार नहीं कर सकता जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर उसकी मुख्य चिंता को अनदेखा करता हो।
6. चीन ने 2013 में इस परियोजना की रूपरेखा पेश की थी जिसका लक्ष्य दक्षिणपूर्वी एशिया, सेंट्रल एशिया, गल्फ रीजन, अफ्रीका और यूरोप को रोड और सागर के नेटवर्क से जोड़ना है। शी चिनफिंग पहले ही कह चुके हैं कि चीन इस प्रॉजेक्ट में 126 अरब डॉलर का निवेश कर सकता है।

विश्व बैंक ने दिया पाक को तगड़ा झटका

भारत के किशनगंगा बांध परियोजना पर पाकिस्तान को विश्व बैंक से तगड़ा झटका लगा है। किशनगंगा परियोजना की शिकायत लेकर विश्व बैंक पहुंचे पाकिस्तान को विवाद पर भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करने की सलाह दी गई है। विश्व बैंक ने पाकिस्तान से कहा है कि वह इस विवाद को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत (आईसीए) में ले जाने के बजाय भारत की तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्त करने की पेशकश को स्वीकार कर ले। भारत ने दो साल पहले ही इस प्रस्ताव की पेशकश की थी।

क्या है

1. विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम ने पिछले हफ्ते पाकिस्तान सरकार को सलाह दी है कि वह मामले को आईसीए में ले जाने के अपने रुख पर नहीं अड़े। पिछले 19 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशनगंगा परियोजना का उद्घाटन किया था। इसके बाद पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल इस परियोजना के खिलाफ विश्व बैंक पहुंचा था।
2. पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीर में किशनगंगा बांध का निर्माण 1960 के सिंधु जल समझौते का उल्लंघन है। वह इस मामले को आईसीए में ले जाना चाहता है।
3. वहीं भारत का कहना है कि पाकिस्तान व उसके बीच मतभेद बांध के डिजाइन को लेकर है इसलिए इसका समाधान किसी तटस्थ विशेषज्ञ द्वारा किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि सिंधु नदी पर पाकिस्तान की 80 प्रतिशत सिंचित कृषि निर्भर करती है। उसका कहना है कि बांध बनाने से न सिर्फ नदी का मार्ग बदलेगा बल्कि पाकिस्तान में बहने वाली नदियों का जल स्तर भी कम होगा।
4. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इस मामले में भारत का प्रस्ताव मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि इससे वह अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में अपना पक्ष खो सकता है। साथ मध्यस्थता के सभी दरवाजे बंद हो सकते हैं।
5. इसके बाद अन्य मामलों में जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी विवाद पैदा होगा तो इसी तरह के निष्पक्ष विशेषज्ञ के जरिए विवाद को सुलझाने की कोशिश की जा सकती है।

फ्लैशबैक

1. भारत ने साल 2007 में पहली बार किशनगंगा पनबिजली परियोजना पर काम शुरू किया था।
2. इसके तीन साल बाद ही पाकिस्तान ने यह मामला हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में उठाया। जहां तीन साल के लिए इस परियोजना पर रोक लगा दी गई।
3. साल 2013 में कोर्ट ने फैसला दिया कि किशनगंगा परियोजना सिंधु जल समझौते के अनुरूप है और भारत ऊर्जा उत्पादन के लिए इसके पानी को मोड़ सकता है।

6. 12 दिसंबर 2016 को विश्व बैंक के अध्यक्ष ने पाकिस्तान के तत्कालीन वित्त मंत्री इशाक डार को चिट्ठी लिखकर यह बताया था कि इस मामले में दखल के लिए वह फिलहाल तैयार नहीं है। साथ ही उसने आईसीए चेयरमैन के साथ ही निष्पक्ष विशेषज्ञ की नियुक्ति की प्रक्रिया को रोकने का फैसला लिया है।
7. इस पर डार ने आपत्ति भी जताई थी लेकिन विश्व बैंक ने इसे अनसुना कर दिया। पाकिस्तान को लगता है कि एक तरफ विश्व बैंक ने आईसीए में यह मामला उठाने से उसके हाथ बांध रखे हैं और दूसरी तरफ उसने भारत को बांध बनाने से नहीं रोका है।

परमाणु हथियार खत्म करने पर राजी हुआ किम जोंग

अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के बीच 12 जून 2018 को ऐतिहासिक मुलाकात हुई। दोनों के बीच दो बार मीटिंग हुई जिसमें पहली मीटिंग 50 मिनट की और दूसरी 41 मिनट की हुई। मीटिंग शुरू होने से पहले दोनों ने गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाकर एक दूसरे का स्वागत किया। मुलाकात के बाद ट्रंप और किम काफी खुश भी नजर आए और इस बैठक को सकारात्मक बैठक करार दिया। दो बार मीटिंग करने के बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने सिंगापुर समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसके अलावा भी ट्रंप-किम ने पीसी में कुछ महत्वपूर्ण बातें कहीं जो निम्न हैं:

क्या है

1. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरियाई लीडर किम जोंग उन ने सिंगापुर समझौता साइन किया।
2. दोनों नेताओं के बीच एक व्यापक दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए हैं। जिसमें परमाणु हथियारों के खाते का अहम करार भी शामिल है।
3. उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ट्रंप ने कहा कि हमने एक 'विशेष अनुबंध' तैयार किया है और निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगी।
4. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किम ने कहा हम एक बड़ी समस्या का हल करने जा रहे हैं, दुनिया एक बड़ा बदलाव देखेगी।
5. साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने राष्ट्रपति ट्रंप से ये पूछा, क्या वह किम जोंग उन को व्हाइट हाउस बुलाएंगे तो उन्होंने जवाब दिया, 'बिल्कुल'
6. डोनाल्ड ट्रंप ने की किम जोंग उन की तारीफ, कहा- उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी रही है हमारी मुलाकात।
7. किम जोंग उन से दोबारा मुलाकात करने के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम फिर मिलेंगे और कई बार मिलेंगे।
8. किम जोंग उन ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात को ऐतिहासिक बताया।
9. प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्रंप ने कहा, किम ने एक दस्तावेज पर साइन करके कोरिया में परमाणु निरस्त्रीकरण का वादा किया है।
10. किम से मुलाकात के बाद बोले ट्रंप, हम नए इतिहास के लिए तैयार हैं। हम नए अध्याय लिखने के लिए तैयार हैं।

ब्रह्मपुत्र नदी का आंकड़ा साझा करने पर चीन राजी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2018 को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत चीन भारत को ब्रह्मपुत्र नदी का आंकड़ा देगा। साथ ही भारत अब चीन को बासमती से अलग दूसरी किस्मों के चावल का भी निर्यात करेगा। समझौते के तहत चीन बाढ़ के मौसम में प्रति वर्ष 15 मई से 15 अक्टूबर के दौरान ब्रह्मपुत्र

नदी के जल से संबंधित आंकड़े भारत को देगा। अन्य मौसम के दौरान नदी का जल स्तर बढ़ने पर भी वह आंकड़े उपलब्ध कराएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से गर्मजोशी से मुलाकात की।

क्या है

1. इस दौरान द्विपक्षीय संबंध को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई। इस बैठक का उद्देश्य वुहान में अनौपचारिक शिखर वार्ता के बाद द्विपक्षीय संबंधों में आ रही प्रगाढ़ता को और बढ़ाना है।
2. एससीओ के शिखर सम्मेलन के इतर दोनों नेताओं की यह बैठक चीन के वुहान शहर में अनौपचारिक बातचीत के करीब छह सप्ताह बाद हुई। इस अनौपचारिक बातचीत का उद्देश्य पिछले साल डोकलाम गतिरोध के बाद दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना और विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को और मजबूत करना था।
3. मोदी एससीओ के सालाना सम्मेलन में शामिल होने के लिए दो दिवसीय दौरे पर 9 जून 2018 दोपहर किंगदाओ पहुंचे।
4. मुलाकात के दौरान मोदी ने वुहान में जिनपिंग के साथ हुई अनौपचारिक वार्ता को भी याद किया। मोदी और जिनपिंग ने 27-28 अप्रैल को वुहान अनौपचारिक वार्ता में किये गये फैसलों के क्रियान्वयन की प्रगति का जायजा भी लिया।
5. वुहान में बातचीत के बाद , मोदी और जिनपिंग ने भविष्य में डोकलाम जैसी स्थिति से बचने पर बात की थी। साथ ही भरोसा और विश्वास पैदा करने के लिए संवाद मजबूत करने के वास्ते अपनी सेनाओं को रणनीतिक दिशानिर्देश जारी करने का फैसला किया था।
6. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन के इतर आज उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की।
7. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट कर बताया कि दोनों नेताओं ने सामरिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए कई विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। दोनों ने आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी बात की।

अमेरिका ने व्यापार पर मिलनेवाली छूट खत्म की

अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन (ईयू), कनाडा और मेक्सिको से आयातित स्टील और ऐल्युमिनियम को शुल्क से मिली छूट खत्म कर दी है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री विलबर रॉस की घोषणा के अनुसार यह रियायत एक जून से समाप्त हो जाएगी। इसके बाद ईयू, कनाडा और मेक्सिको ने जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने मार्च में स्टील पर 25 फीसदी और ऐल्युमिनियम पर 15 फीसदी आयात शुल्क लगाने की घोषणा की थी। 30 अप्रैल को उसने इन देशों के लिए अस्थायी रियायत 30 दिनों के लिए बढ़ा दी थी, ताकि दोनों पक्षों के बीच बातचीत किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके।

क्या है

1. ईयू के प्रमुख जीन क्लॉड जुंकर ने ब्रसलज में कहा कि ईयू जल्दी ही कड़े अमेरिकी शुल्क के खिलाफ जवाबी घोषणा करेगा। मेक्सिको ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है।
2. दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का कहना है कि उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते (नाफ्टा) पर संतुलित समझौते के अलावा कोई और विकल्प मौजूद नहीं है।
3. मेक्सिको और कनाडा से नाफ्टा पर फिर से बातचीत जारी है। राष्ट्रपति ने एक बयान में कहा कि व्यापार के मामले में अमेरिका का कई दशकों तक फायदा उठाया गया है लेकिन वह दिन अब लद गए हैं।

4. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को संदेश पहुंचा दिया गया है कि अमेरिका संतुलित समझौते पर ही राजी होगा या फिर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
5. जस्टिन इससे पहले अमेरिकी उप राष्ट्रपति माइक पेस को नाफ्टा की बातचीत ठप्प पड़ने के लिए जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। उनके (जस्टिन के) अनुसार पेस ने एक ऐसे समझौते की मांग की थी जो पांच वर्ष में स्वयं खत्म हो जाए।

नर्सिंग क्षेत्र में परस्पर मान्यता सहमति पत्र (एमआरए) पर हस्ताक्षर

भारत ने सिंगापुर के साथ नर्सिंग क्षेत्र में परस्पर मान्यता सहमति पत्र (एमआरए) पर हस्ताक्षर किये हैं। एफटीए सहयोगी के साथ किया जाने वाला यह पहला एमआरए है। सिंगापुर ने 7 भारतीय नर्सिंग संस्थानों को मान्यता देने पर सहमति जताई। इसने स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को विदेशी बाजारों तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया है।

क्या है

1. इससे भारत का अन्य देशों के साथ भी ऐसे परस्पर मान्यता समझौते करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
2. भारत और सिंगापुर ने भारत-सिंगापुर सीईसीए की दूसरी समीक्षा का निष्कर्ष निकाला जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान आधिकारिक रूप से घोषित किया गया।
3. दोनों ही देश 2010 से लंबित विभिन्न अनसुलझे मुद्दों पर दूसरी समीक्षा में आम सहमति तक पहुंच सकते हैं।
4. दोनों देशों के बीच व्यापार में विस्तार के उद्देश्य से भारत और सिंगापुर ने टैरिफ रियायतों, मूल स्थान से संबंधित नियमों को उदार बनाने तथा उत्पाद विशेष नियम (पीएसआर) बनाने पर सहमति व्यक्त की है।

सिंगापुर ई-गवर्नमेंट भारत में कौशल विकास कार्यक्रमों को देगी पंख

सिंगापुर ई-गवर्नमेंट लीडरशिप सेंटर (ईजीएल) देश की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिस्टम्स साइंस (एनयूएस-आईएसएस) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), भारत के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत सहयोग करने के लिए एक साथ आए हैं, ताकि भारत में कर्मचारियों का कौशल विकास हो सके। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सिंगापुर यात्रा (31 मई से 2 जून 2018) के दौरान दोनों देशों के बीच भारत के कार्यबल में कौशल को बढ़ाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे। इस दौरान तय हुआ था कि दोनों देश उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रमों को विकसित और कार्यान्वित करने के लिए डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। विशेष रूप से न्यू ऐज टेक्नोलॉजी और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के क्षेत्रों में भी सहयोग करेंगे।

क्या है

1. एनएसडीसी कौशल और विकास के भविष्य की पहचान करने तथा भारत में आवश्यक दक्षताओं को विकसित करने के लिए एनयूएस जैसे अग्रणी संस्थानों के साथ मिलकर काम करने का प्रयास करती है।
2. वर्तमान में नई आयु के कौशल की बड़ी मांग है, जो हमारे युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है। एनयूएस-आईएसएस के साथ इस सहयोग के माध्यम से हम प्रशिक्षण के अवसर पैदा करेंगे, जो हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और दुनिया में तकनीकी परिवर्तनों के साथ तालमेल रखने में हमारी सहायता करें।
3. एनयूएस-आईएसएस अपने ई-गवर्नमेंट लीडरशिप सेंटर के माध्यम से एनएसडीसी और उद्योग संचालित निकायों को सलाह देंगे, जो क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) के रूप में जाना जाता है और भारत में मौजूदा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उभरती प्रौद्योगिकियों को शामिल करने के लिए रणनीतियों को विकसित करता है।

यूएन रिपोर्ट को भारत ने बताया घातक

भारत की तरफ से कश्मीर पर जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज कर दिया गया है। रिपोर्ट में भारत पर कथित तौर पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल (एलओसी) के दोनों तरफ कश्मीर में मानवाधिकार की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी अपनी तरह की पहली रिपोर्ट जारी की गई है। खास बात यह है की यह रिपोर्ट आल हुसैन द्वारा तैयार की गई है रिपोर्ट में ऑफिस ऑफ द हाई कमीश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स (ओएचसीएचआर) जैद अल हुसैन ने कहा, भारतीय सुरक्षा बलों को अधिकतम संयम का प्रयोग करने के लिए कहा गया, और भविष्य में विरोधों से निपटने के दौरान बल के उपयोग को नियंत्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानकों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।

क्या है

1. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय अधिकारियों ने कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा बल के अत्यधिक उपयोग के कई उदाहरणों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाए गए हैं।
2. यह रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है, जब भारत की तरफ से रमजान सीजफायर का ऐलान किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस रिपोर्ट को 'घातक, प्रवृत्त, भारतीय संप्रभुता का उल्लंघन, बड़े पैमाने पर असत्यापित जानकारी का संकलन, अत्यधिक पूर्वाग्रह और झूठ से प्रेरित' बताया है।
3. अल हुसैन द्वारा तैयार की गई यह रिपोर्ट उनकी अंतिम रिपोर्टों में से एक होगी। हुसैन इस साल अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और इसके बाद यूएन जनरल असेंबली नया प्रमुख नियुक्त करेगी।
4. न तो भारत और न ही पाकिस्तान ने ओएचसीएचआर कार्यालय को कश्मीर तक पहुंचने की इजाजत दी, इसलिए हुसैन ने कहा कि यह रिपोर्ट 'रिमोट मॉनिटरिंग' का नतीजा है।
5. जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर में भारत की सक्रिय उपस्थिति है, लेकिन भारत के राजदूत देश की इमेज खराब करने वाली रिपोर्ट की जानकारी हासिल करने में असफल रहे। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने ओएचसीएचआर को अपने विरोध की जानकारी दे दी है।
6. यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के पूर्व वाइस प्रेजिडेंट दिलीप सिन्हा ने बताया, 'यह रिपोर्ट झूठ का पुलिंदा है क्योंकि यह ओआईसी (ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन) कश्मीर को लेकर पूर्वाग्रह के साथ तैयार की गई है। यह उस देश की आलोचना करना है, जो अपने लोगों को अधिकार देती है, साथ ही एनजीओ और मीडिया को काम करने की छूट देती है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है।'

अर्थशास्त्र

आउटकम ऑडिट

अब तक सिर्फ योजनाओं के अनुपालन और प्रदर्शन का ऑडिट करने वाला भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैंग) आने वाले समय में इस बात की भी ऑडिट करेगा कि कोई योजना अपने मकसद में कामयाब हुई भी या नहीं। कैंग ने इस आउटकम ऑडिट के लिए खुद को सक्षम बनाने के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। कैंग अगले साल से आउटकम ऑडिट शुरू कर सकता है। कैंग के आला अधिकारी ने कहा कि कैंग ने समय के साथ अपनी ऑडिटर की भूमिका में विस्तार किया है।

क्या है

1. एक समय था कि जब कैंग सिर्फ कंप्लायंस ऑडिट करता था कि कोई विभाग नियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं।

2. एक दशक पहले कैंग ने दायरा बढ़ाते हुए परफॉर्मेंस ऑडिट शुरू किया था। इसी की वजह से 2जी घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला और कोलगेट जैसे घोटाले सामने आए थे।
3. अधिकारी ने कहा कि अब अपना दायरा और बढ़ाते हुए कैंग किसी योजना की कामयाबी या नाकामी का भी ऑडिट करने की तैयारी कर रहा है। अधिकारी ने बताया कि वर्तमान कैंग राजीव महर्षि खुद इसमें रुचि ले रहे हैं। उन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे शुरू करने का निर्देश दिया है।
4. आउटकम ऑडिट शुरू करने में सबसे बड़ी समस्या ये है कि कैंग के वर्तमान अधिकारियों के पास आउटकम ऑडिट करने का अनुभव नहीं है।
5. साथ ही आउटकम ऑडिट के लिए काफी संख्या में मानव संसाधन की जरूरत होगी, जो कैंग के पास नहीं है। सूत्रों की मानें तो इस अड़चन को दूर करने के लिए कैंग अपने अधिकारियों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण देगा। इसके अलावा किसी बाहरी एजेंसी को सर्वे जैसे कामों के लिए भी नियुक्त किए जाने पर भी चर्चा चल रही है।
6. आउटकम ऑडिट का सबसे अधिक फायदा लोगों से सीधे जुड़े मंत्रालयों जैसे कि स्वास्थ्य एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय को होगा।
7. आउटकम ऑडिट होने से वे जान सकेंगे कि उनकी योजनाओं से वास्तव में लाभार्थियों को कितना लाभ पहुंचा। इससे वे अपनी गलतियां सुधार सकेंगे और योजना का लक्ष्य पूरा हो सकेगा।

शहरी गरीबों के लिए मकानों के निर्माण को मंजूरी

केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 1.5 लाख मकानों के निर्माण को मंजूरी दी है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने यह जानकारी दी। मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया कि 2,209 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता युक्त 7,227 करोड़ रुपये के निवेश के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत शहरी गरीबों के हित के लिए 1.5 लाख मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।

क्या है

1. केन्द्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति की 34 वीं बैठक में इस आशय की स्वीकृति दी गई।
2. आंध्र प्रदेश के लिए 56,512 मकानों को मंजूरी दी गई जबकि उत्तर प्रदेश को 23,060 मकान मिले हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश के लिए 17,920 मकानों को मंजूरी दी गई है। झारखंड के लिए 14,526 मकानों और महाराष्ट्र के लिए 13,506 मकानों की स्वीकृति दी गई है।
3. अन्य जिन राज्यों में मकानों की मंजूरी दी गई है उनमें छत्तीसगढ़ , राजस्थान , ओडिशा , पंजाब और असम शामिल हैं।

दिवालिया प्रक्रिया में कंपनियों पर निगरानी बढ़ाएगा सेबी

पूजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही कंपनियों पर 11 जून 2018 से अतिरिक्त निगरानी व्यवस्था अमल में लाएगा। प्रमुख शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने यह जानकारी दी है। बीएसई पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल एबीजी शिपयार्ड, एमटेक ऑटो, भूषण स्टील, जेपी इन्फ्राटेक, इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स, मंधाना इंडस्ट्रीज, मेनेट इस्पात एंड एनर्जी, रुचि सोया इंडस्ट्रीज, सुप्रीम टेक्स मार्ट, वर्धमान इंडस्ट्रीज और आरईआइ एग्री समेत 75 कंपनियां इंसॉल्वेंसी एंड बैकप्री कोड (आइबीसी) के तहत दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही हैं।

क्या है

1. बाजार की अक्षुण्णता और निवेशकों के हित सुरक्षित रखने के लिए सेबी और शेयर बाजार निगरानी के और मजबूत तंत्र लागू कर रहे हैं। इनमें प्राइस बैंड में कमी और सिक्युरिटीज को समय-समय पर ट्रेड-टू-ट्रेड कैटेगरी में लाने जैसे उपाय शामिल हैं।

2. पहले से लागू निगरानी तंत्र को मजबूती देने के लिए सेबी और शेयर बाजारों की संयुक्त निगरानी बैठकें हुई हैं। उनमें हुई चर्चाओं पर अमल करते हुए आइबीसी के तहत समाधान प्रक्रिया (आइआरपी) से गुजर रही कंपनियों के लिए 11 जून 2018 से अतिरिक्त निगरानी तंत्र अमल में लाए जा रहे हैं।
3. इसके तहत आइबीसी प्रक्रिया से गुजर रही कंपनियों की मॉनिटरिंग पूर्व निर्धारित मानदंडों के हिसाब से होगी। मानदंडों पर खरा उतरने के बाद सिक््युरिटीज पर 100 फीसद मार्जिन वसूल की जाएगी।
4. उन सिक््युरिटीज को फिर से निष्पक्ष कसौटियों पर रखा जाएगा और सभी कसौटियों पर खरा उतरने के बाद उन्हें ट्रेड-टू-ट्रेड सेगमेंट में रखा जाएगा। बीएसई ने यह भी कहा कि नवीनतम निगरानी तंत्र पूर्व में समय-समय पर लागू निगरानी के अतिरिक्त होंगे।

सबसे तेज ग्रोथ वाली अर्थव्यवस्था बना भारत

भारत ने सबसे तेज ग्रोथ वाली अर्थव्यवस्था के अपने रुतबे को बरकरार रखा है। अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के दौरान 7.2 फीसद की जीडीपी ग्रोथ से बढ़ने वाले भारत की जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 2017-18 की आखिरी तिमाही में 7.7 फीसद रही है। ग्रोथ के मामले में भारत ने एक बार फिर से चीन को पछाड़ा है। गौरतलब है कि जनवरी-मार्च (2017-18) तिमाही के जीडीपी आंकड़े 31 मई 2018 को ही जारी किए गए हैं। ये आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी विभाग जारी करता है।

क्या है

1. मार्च तिमाही में भारत फिर हुआ चीन से आगे: मार्च तिमाही में भारत ग्रोथ के मामले में एक बार फिर से चीन से आगे हो गया है। वित्त वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में जहां एक ओर भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7 फीसद रही है वहीं चीन की ग्रोथ 6.8 फीसद ही रही है। बीते वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में देश की विकास दर 7.2 फीसद रही थी जो कि बीती पांच तिमाहियों में सबसे ज्यादा रही। इसके साथ ही भारत की विकास दर एक बार दुनिया में सबसे तेज हो गई थी। इस तिमाही में चीन की विकास दर 6.8 फीसद रही थी।
2. जनवरी मार्च तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ: नोटबंदी और जीएसटी के बाद अर्थव्यवस्था फिर तेज रफ्तार पर आ गई है। वित्त वर्ष 2017-18 की अंतिम तिमाही यानी जनवरी-मार्च में कृषि, मैन्यूफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के शानदार प्रदर्शन की बदौलत देश की विकास दर बढ़कर 7.7 फीसद हो गई है, जो बीती सात तिमाही यानी करीब पौने दो साल में सबसे तेज है। जीडीपी की तिमाही वृद्धि दर नोटबंदी से पहले की तिमाही की रफ्तार से भी अधिक है।
3. खास बात यह है कि कई तिमाहियों से सुस्त पड़ी निवेश की रफ्तार भी अब बढ़ने लगी है। ऐतिहासिक परोक्ष कर सुधार जीएसटी लागू होने के बाद मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र की वृद्धि दर लगातार बढ़ रही है। पहले ही विकास की रफ्तार में भारत से पिछड़ गए चीन की दर जनवरी-मार्च तिमाही में 6.8 फीसद ही रही।
4. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने 2017-18 की चौथी तिमाही और पूरे वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़े जारी किए। 2017-18 में पूरे साल के दौरान देश की जीडीपी 13.11 लाख करोड़ रुपये रही, जो 2016-17 की तुलना में 6.7 फीसद अधिक है।

नौ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बनाया रिकवरी प्लान

पीसीए के दायरे में रखे गए 11 में से नौ सार्वजनिक बैंकों ने सरकार के पास दो वर्षों की रिकवरी योजना दाखिल कर दी है। एक अधिकारी ने कहा कि इसके तहत ये बैंक अपनी सहायक शाखाओं में हिस्सेदारी की बिक्री और कॉर्पोरेट कर्ज घटाने पर काम करेंगे। इन नौ बैंकों में देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

(यूबीआइ), कॉरपोरेशन बैंक, आइडीबीआई बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया (बीओआइ), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक (आइओबी), ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल हैं।

क्या है

1. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले महीने 11 सार्वजनिक बैंकों को अपनी माली हालत दुरुस्त करने और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) द्वारा जारी पूंजी पर्याप्तता मानकों का पालन करने के लिए कार्ययोजना दाखिल करने को कहा था।
2. बैंकों द्वारा दाखिल योजना में लागत घटाने, शाखाओं की संख्या कम करने, विदेशी शाखाएं बंद करने तथा कॉरपोरेट जगत के साथ-साथ अन्य कर्जदारों को जोखिम भरे कर्ज की मात्रा घटाने जैसे उपाय शामिल हैं।
3. गौरतलब है कि प्रांट करेक्टिव एक्शन (पीसीए) के दायरे में रखे गए बैंकों पर लाभांश वितरण और मुनाफे के भुगतान के मोर्चे पर कई तरह के प्रतिबंध लगे होते हैं।
4. ऐसे बैंकों के मालिक (सरकार) को इनमें पूंजी लगाने को कहा जा सकता है। इसके अलावा उन्हें शाखाओं की संख्या बढ़ाने से रोका जा सकता है। इनके निदेशकों को दी जाने वाली फीस भी सीमित की जा सकती है।
5. सितंबर तक 13,000 करोड़ रुपये जुटाएगा पीएनबी: नीरव मोदी घोटाले का दंश झेल रहे पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने इस वर्ष सितंबर के अंत तक 13,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है।
6. यह रकम बैंक की सहायक शाखा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में हिस्सेदारी बेचने समेत फंसे कर्जों (एनपीए) की रिकवरी के जरिये जुटाई जाएगी। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में पीएनबी की 39.08 फीसद हिस्सेदारी है।

विश्व बैंक ने अटल भूजल योजना को अनुमति प्रदान की

विश्व बैंक ने 6000 करोड़ की लागत से जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना को अनुमति प्रदान की है। योजना को विश्व बैंक की सहायता से 2018-20 से 2022-23 की पांच वर्षीय कालावधि में कार्यान्वित किया जाना है। मंत्रालय की वित्त व्यय समिति पहले ही योजना के प्रस्ताव की अनुशंसा कर चुकी है एवं परियोजना के लिये मंत्रालय जल्द ही मंत्रिमण्डल की मंजूरी लेगा।

क्या है

1. देश के बड़े भाग में भूजल संसाधनों की गंभीर कमी दूर करने के लिये मंत्रालय ने अटल भूजल योजना का निर्माण किया है। योजना का उद्देश्य देश के प्राथमिक क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी से भूजल प्रबंधन की स्थिति में सुधार करना है।
2. योजना के अंतर्गत पहचान किये गये प्राथमिक क्षेत्र गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में पड़ते हैं।
3. यह राज्य भारत में भूजल के मामले में अत्यधिक शोषित, संकटमय एवं अर्द्ध संकटमय खंडों का लगभग 25% निरूपित करते हैं। यह राज्य भारत में पाये जाने वाले दो बड़े प्रकार के भूजल निकायों- जलोढ़ एवं हार्ड रॉक जलभूत को कवर करते हैं एवं भूजल प्रबंधन में सांस्थानिक तैयारी एवं अनुभव के मामले में यह आत्मनिर्भर हैं।
4. योजना के अंतर्गत भूजल संचालन हेतु जिम्मेदार संस्थानों को बेहतर बनाने एवं भूजल प्रबंधन में पानी के प्रभावी उपयोग एवं संरक्षण को बढ़ावा देने वाला व्यवहारगत परिवर्तन लाने के लिये सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिये धनराशि प्रदान की जाएगी।
5. यह योजना पहचान किये गए प्राथमिक क्षेत्रों में योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रोत्साहन देकर प्रदेशों में जारी मौजूदा सरकारी योजनाओं के सम्मिलन की सुविधा भी प्रदान करेगी।

6. योजना के क्रियान्वयन से इन प्रदेशों के 78 जिलों में लगभग 8350 ग्राम पंचायतों के लाभान्वित होने की आशा है। योजना के अंतर्गत धनराशि अनुदान के रूप में भागीदारी करने वाले प्रदेशों को उपलब्ध करा दी जाएगी।
7. भूजल प्रबंधन में सक्रिय सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना योजना के बड़े उद्देश्यों में शामिल है। योजना के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों जैसे वॉटर यूजर एसोसिएशन, भूजल के आंकड़ों की निगरानी एवं वितरण, जलसंबंधी आय-व्यय, ग्राम पंचायतों के अनुरूप जल सुरक्षा योजनाओं की तैयारी व कार्यान्वयन एवं चिरस्थायी जल प्रबंधन से संबंधित आईईसी गतिविधियों में समुदायों की सक्रिय भागीदारी प्रस्तावित की गई है।
8. सार्वजनिक वित्तपोषण की प्रभावोत्पादकता में सुधारके लिये एवं भागीदार राज्यों में भूजल पर विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के लिये नीचे से ऊपर भूजल योजना की प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी से भी मदद मिलने की आशा है।
9. योजना के कार्यान्वयन से अनेक सकारात्मक परिणाम मिलने की आशा है जैसे भूजल के बारे में बेहतर समझ, भूजल में गिरावट से संबंधित विषयों पर ठोस एवं समेकित समुदाय-आधारित रुख, नयी एवं पुरानी योजनाओं के सम्मिलन से संधारणीय भूजल प्रबंधन, पानी के उपयोग से जुड़ी प्रभावी प्रक्रियाओं को अपनाने से सिंचाई में लगने वाले भूजल के इस्तेमाल में कमी एवं लक्षित क्षेत्रों में भूजल संसाधनों में बढ़ोतरी।

विज्ञान एवं तकनीकी

उल्का पिंड गिरने से बना राजस्थान का रामगढ़ क्रेटर

राजस्थान के बारां जिले में वैज्ञानिकों और पर्यटकों के लिए कौतूहल के साथ आकर्षण का केंद्र रहे रामगढ़ क्रेटर के बारे में विशेषज्ञों का दावा है कि यह उल्का पिंड गिरने से ही बना है। यह क्रेटर 3.2 किलोमीटर के दायरे में फैला है और सबसे पहले इसकी खोज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वर्ष 1869 में की थी। करीब एक सदी बाद 1960 में जियोलॉजिकल सोसायटी ऑफ लंदन ने इसे क्रेटर तो घोषित किया, लेकिन इसके बनने के बारे में हमेशा ही अलग-अलग विचार सामने आते रहे हैं।

क्या है

1. अब हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हैरिटेज (इंटेक) के केंद्रीय कार्यालय के चार विशेषज्ञों

क्या होते हैं क्षुद्रग्रह

1. अंतरिक्ष में मौजूद टूटे हुए तारों और क्षुद्रग्रहों के छोटे छोटे हिस्सों को उल्कापिंड कहते हैं। ये कचरे की तरह अंतरिक्ष में बिखरे रहते हैं। जब ये धरती के माहौल में प्रवेश करते हैं, तो उल्कापिंड कहलाते हैं।
2. ज्यादातर उल्कापिंड पर्यावरण में घुसने के बाद ही बिखर जाते हैं, जबकि कुछ घर्षण को बर्दाश्त कर लेते हैं और एक ही टुकड़े में गिरते हैं।
3. धरती पर गिरते हुए इनका तापमान 3 हजार डिग्री से भी अधिक तक पहुंच जाता है। आपको बता दें कि 2000 से 2013 के बीच ही धरती से 26 ऐसे क्षुद्रग्रह टकराए जिनकी विस्फोटक क्षमता 1 से 600 किलोटन टीएनटी के बीच थी।
4. कैलिफोर्निया में स्थित बी-612 फाउंडेशन के संस्थापक और सीईओ एड लू मानते हैं कि कई क्षुद्रग्रहों का पता समय रहते लगा लिया जाता है। उनका यह भी कहना है कि कुछ क्षुद्रग्रह न सिर्फ किसी देश को तबाह कर सकते हैं बल्कि पूरे महाद्वीप का भी अंत कर सकते हैं।
5. उनके मुताबिक हम नहीं जानते कि अगली टक्कर कहां और कब हो सकती है इसलिए अगर हम अब तक शहरों को तबाह करने वाले प्रलयकारी क्षुद्रग्रहों की टक्कर से बचे हुए हैं तो यह सिर्फ संयोग की बात है।

- की टीम ने इसका दौरा किया और इसके बनने से संबंधी प्रमाण एकत्र किए हैं।
2. टीम के सदस्य प्रोफेसर विनोद अग्रवाल का दावा है कि **करीब 75 हजार करोड़ वर्ष पूर्व तीन किलोमीटर लंबा एक उल्का पिंड यहां गिरा होगा** और इसी से यहां चार किलोमीटर डाइमीटर की खाई बन गई।
 3. विशेषज्ञों के अनुसार हमारे देश में दो ही क्रैटर हैं। इनमें से एक महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में और दूसरा मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है।
 4. रामगढ़ क्रैटर के बीच का भाग उठा हुआ है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के मापदंडों के अनुसार यह बताता है कि यह उल्का पिंड से बना है।
 5. यह भारत का दुर्लभ स्थान है, जो कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। जब कोई चीज नीचे गिरती है तो उसका समान असर दूसरी तरफ पड़ता है। इस क्रैटर में बीच का उठा हुआ हिस्सा इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि यह उल्का पिंड से बना है।
 6. कनाडा स्थित ग्लोबल एजेंसी जल्द ही इसे दुनिया के 191 और भारत के तीसरे क्रैटर के रूप में मान्यता देगी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इंटैक के बारां चौपटर से जुड़े जितेंद्र कुमार शर्मा का कहना है कि इसके बाद राजस्थान और बारां जियोलाॉजिकल ग्लोबल मैप पर आ जाएंगे। उन्हें उम्मीद है कि 2020 में हो रही वर्ल्ड जियोलाॉजिकल सेमिनार में रामगढ़ क्रैटर को मान्यता मिल जाएगी।

भारतीय वैज्ञानिकों ने 'के2-236' खोजा

भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने शनि जितने बड़े एक ग्रह की खोज का दावा किया है। इस खोज के बाद भारत सितारों के आसपास के ग्रह खोजने वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है। यह खोज अहमदाबाद स्थित फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी (पीआरएल) के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी तकनीक से बने पीआरएल एडवांस रेडियल-वेलोसिटी अबू-स्काई सर्च (पारस) की मदद से की है।

क्या है

1. हालांकि इस ग्रह के बारे में कुछ जानकारीयां अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के यान केपलर 2 ने भी भेजी थीं। मगर उससे इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी।
2. इसके बाद पारस स्पेक्टोग्राफ के जरिए भारतीय वैज्ञानिकों ने ग्रह के आकार का आकलन किया था। इस दौरान उन्हें ग्रह के 60-70 प्रतिशत हिस्से पर बर्फ, सिलिकेट और लोहे जैसे तत्वों का पता चला।
3. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपनी वेबसाइट पर इस नई खोज के बारे में बताया है। पोस्ट में इस ग्रह को पृथ्वी के आकार से 27 गुना बड़ा बताया गया है।
4. वहीं, इसका अर्धव्यास (त्रिज्या) पृथ्वी के अर्धव्यास से छह गुना बड़ा है। सूरज जैसे सितारे के इर्द-गिर्द चक्कर लगाता यह ग्रह पृथ्वी से 600 प्रकाश वर्ष दूर है।
5. इसरो के मुताबिक ग्रह के सूरज का नाम 'एपिक 211945201' या 'के2-236' है। वहीं, ग्रह को 'एपिक 211945201बी' या 'के2-236बी' नाम दिया गया है।
6. रिपोर्ट के मुताबिक यह ग्रह अपने सितारे के काफी नजदीक है इसलिए इसकी सतह का तापमान करीब 600 डिग्री सेल्सियस है।
7. इसरो के मुताबिक यह पृथ्वी से सूरज की दूरी के मुकाबले अपने सूरज से सात गुना नजदीक है। इस वजह से यहां जीवन की उत्पत्ति नहीं हो सकती।
8. वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ग्रह की खोज के बाद ऐसे और ग्रहों के बारे में जानने में मदद मिलेगी जो अपने सूरज के काफी नजदीक हैं।

कार्बन डाईऑक्साइड का इंजेक्शन

पेट पर जमा चर्बी की परत सबसे जिद्दी होती है। वजन घटाने की कोशिशों में लगे लोगों के लिए तोंद कम करना किसी चुनौती से कम नहीं होता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए विशेषज्ञों ने एक नई तकनीक ईजाद करने का दावा किया है।

क्या है

1. डाइटिंग और भारी-भरकम व्यायाम कर थक चुके लोगों के लिए कार्बोक्सीथेरेपी तकनीक पेश की है। इस तकनीक में शरीर में कार्बन डाईऑक्साइड गैस इंजेक्शन के जरिए प्रवेश कराई जाएगी।
2. अमेरिका के इलिनॉय स्थित नॉर्थवेस्टर्न मेडिसिन ने यह अध्ययन किया है। शोधकर्ताओं का दावा है कि इंजेक्शन के जरिए कार्बन डाईऑक्साइड गैस देने से पेट की चर्बी को कम किया जा सकता है।
3. कार्बोक्सीथेरेपी के लिए हुए क्लिनिकल अध्ययनों में कहा गया है कि इससे पेट के आकार को दुरुस्त करने में लंबे समय में आराम मिलेगा।
4. डॉ. आलम का कहना है कि इंजेक्शन के जरिए कार्बन डाईऑक्साइड देने से माइक्रोसर्कुलेशन में बदलाव होता है और चर्बी वाली कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं। यह अध्ययन जर्नल ऑफ अमेरिकन अकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी में प्रकाशित हुआ है।

धरती से चंद्रमा के दूर जाने के कारण लंबे हो रहे हैं दिन

चंद्रमा के पृथ्वी से दूर जाने के कारण हमारे ग्रह पर दिन लंबे होते जा रहे हैं। एक अध्ययन में यह बात सामने आयी है कि 1.4 अरब वर्ष पहले धरती पर एक दिन महज 18 घंटे का होता था। पत्रिका प्रोसिडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित यह अध्ययन चंद्रमा से हमारे ग्रह के रिश्ते के गहरे इतिहास को पुनः स्थापित करता है।

क्या है

1. इसमें पाया गया कि 1.4 अरब वर्ष पहले चंद्रमा पृथ्वी के ज्यादा करीब था और उसने पृथ्वी के अपनी धूरी के चारों ओर घूमने के तरीके को बदला।
2. अमेरिका में विस्कॉन्सिन-मैडिसन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीफन मेयर्स ने कहा कि जैसे-जैसे चंद्रमा दूर जा रहा है तो धरती एक स्पिनिंग फिगर स्केटर की तरह व्यवहार कर रही है जो अपनी बाहें फैलाने के दौरान अपनी गति कम कर लेता है।
3. ब्रह्मांड में पृथ्वी की गति अन्य ग्रहों से प्रभावित होती है जो उस पर बल डालते हैं जैसे कि अन्य ग्रह और चंद्रमा। वैज्ञानिकों ने लाखों वर्षों की अवधि में पृथ्वी की इस गति का अवलोकन किया और इससे वह पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी और दिन के घंटों का पता लगा पाए।

अफ्रीका के आसमान में टूटकर बिखरा क्षुद्रग्रह

अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक धरती से टकराने वाला पत्थर के आकार का एक क्षुद्रग्रह वायुमंडल में बिखर गया और बोत्सवाना के आसमान को जगमग करता नजर आया। दो मीटर चौड़ाई वाले इस क्षुद्रग्रह का पहली बार कैताल्लिना स्काय सर्वे द्वारा दो जून को पता लगाया गया था।

क्या है

1. इस क्षुद्रग्रह को 2018 एलए के तौर पर चिह्नित किया गया था। इसका आकार इतना छोटा था कि माना जा रहा था कि यह धरती के वातावरण में सुरक्षित तरीके से टूट कर बिखरेगा।

- हालांकि इसके टूट कर बिखरने का सटीक अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं था लेकिन हिंद महासागर के आस-पास दक्षिण अफ्रीका से लेकर न्यू गिनी तक की पट्टी पर इसके बिखरने की संभावना जताई गई थी।
- 3 जून 2018 शाम अफ्रीका के बोत्सवाना में आग के एक चमकीले गोले का नजर आना इस अनुमान के साथ मेल खा गया। इस क्षुद्रग्रह ने 17 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से धरती के वातावरण में शाम करीब पौने सात बजे (बोत्सवाना स्थानीय समयानुसार) प्रवेश किया।

मंगल पर मिला जीवन का अब तक का सबसे बड़ा प्रमाण

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा मंगल ग्रह के रहस्यों पर से पर्दा उठाने के मिशन पर लगे क्यूरियोसिटी रोवर की ताजा खोज से बेहद उत्साहित है। नासा ने रोवर की नई खोज के बारे में दुनिया को एक प्रेस कांफ्रेंस कर जानकारी दी। नासा ने बताया कि उसके क्यूरियोसिटी रोवर को लाल ग्रह पर करीब 3 अरब साल पुराने कार्बनिक अणु मिले हैं। नासा इस खोज से काफी उत्साहित है, इसे कई सालों पहले यहां जिंदगी होने के सबूत के तौर पर देखा जा रहा है।

क्या है

- नासा ने 2012 में मंगल ग्रह पर रोबोट एक्सप्लोरर क्यूरियोसिटी रोवर भेजा था, जो तभी से वहां खोज में लगा हुआ है। 3 अरब साल से अधिक पुराने पत्थरों को सिर्फ 2 इंच तक खोदने से दो अलग-अलग तरह के जैविक अणु मिले।
- दरअसल पहले जब यह ग्रह आज की तुलना में गर्म और गीला था, तब वहां गैले क्रेटर एक झील जैसे रूप में दिखता था जो अब एक चट्टान बन गया है और उसी चट्टान के पत्थर को खोदने से ये जैविक प्रमाण मिले हैं।
- नासा ने बताया कि लाल ग्रह पर जीवन की मौजूदगी के अब तक के सबसे बेहतरीन प्रमाण मिले हैं। हालांकि नासा के सौर मंडल अन्वेषण प्रभाग के निदेशक पॉल महाफी का कहना है कि अभी ये पुष्टि नहीं की जा सकती कि इन मॉलीक्यूलस का जन्म कैसे हुआ।
- हालांकि इन सबूतों के आधार पर यह जरूर कहा जा सकता है कि अरबों साल पहले मंगल ग्रह पर गैले क्रेटर के अंदर पानी की एक उथली झील थी जिसमें जीवन के लिए जरूरी सभी तत्व शामिल थे।
- कार्बनिक अणुओं के मिलने से मंगल पर कभी जीवन होने के संकेत मिलते तो हैं, मगर इस बात से भी इंकार नहीं किया जा रहा कि ये किसी उल्कापिंड की टक्कर या किसी अन्य जरिए से आए हों।
- मैरीलैंड में नासा के गोडार्ड स्पेस सेंटर के साथ जेनिफर इंगेनब्रोड ने कहा कि मंगल ग्रह पर पाए गए कार्बनिक अणु जीवन होने के तथ्य को पूरी तरह से प्रमाणित नहीं करते क्योंकि वे गैर-जैविक चीजों से आ सकते हैं।
- हालांकि ये जीवन की खोज के लिए महत्वपूर्ण प्रमाण जरूर है। नासा ने इस बात पर भी जोर दिया है कि इस तरह के कण मंगल ग्रह पर काल्पनिक माइक्रोबियल जीवन के लिए खाद्य स्रोत हो सकते हैं।
- इससे पहले क्यूरियोसिटी रोवर को लाल ग्रह पर 2013 में पानी होने के संकेत मिले थे। नासा विशेषज्ञों को मंगल पर कार्बनिक अणुओं के अलावा उसके वातावरण में मिथेन गैस की मौजूदगी के भी प्रमाण मिले हैं। कार्बनिक अणु के आलावा मंगल के वातावरण की मिथेन में मौसमी उतार-चढ़ाव के प्रभाव देखे गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि धरती पर जितनी भी मिथेन बनती है, वह जैविक प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप बनती है। हालांकि वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि अभी दो बातों को एक-दूसरे से जोड़ना जल्दबाजी हो सकता है।

25 सालों में अंटार्कटिका की बर्फ 30 खरब टन पिघली

अंटार्कटिका में बर्फ चिंताजनक दर से पिघल रही है। साल 1992 के बाद से करीब 30 खरब टन बर्फ पिघल चुकी है। हिम विशेषज्ञों के एक अंतरराष्ट्रीय दल ने एक नए अध्ययन में कहा कि सदी की पिछली तिमाही में अंटार्कटिका के दक्षिणी छोर में पानी में इतनी ज्यादा बर्फ पिघल चुकी है कि टेक्सस में करीब 13 फीट तक जमीन

डूब गई है। दक्षिणी छोर में बर्फ की यह चादर जलवायु परिवर्तन की मुख्य संकेतक है। यह अध्ययन नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुआ।

क्या है

1. अध्ययन के मुताबिक साल 1992 से 2011 तक अंटार्कटिका में एक साल में करीब 84 अरब टन बर्फ पिघली। साल 2012 से 2017 तक बर्फ पिघलने की दर प्रति वर्ष 241 अरब टन से भी ज्यादा हो गई।
2. अध्ययन से जुड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफॉर्निया इरविन की इजाबेल वेलिकोगना ने कहा, 'मुझे लगता है कि हमें चिंतित होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हताश होना चाहिए।
3. चीजें हो रही हैं। हमारी उम्मीदों से अधिक तेजी से चीजें हो रही हैं। पश्चिम अंटार्कटिका का वह हिस्सा ढहने की स्थिति में है। इसी हिस्से में सबसे ज्यादा बर्फ पिघली है।'

विविध

'डेक्कन क्वीन' रेल सेवा के आज 88 वर्ष संपन्न हुए

01 जून, 1930 को महाराष्ट्र के दो प्रमुख शहरों के बीच भारतीय रेल की अग्रणी 'डेक्कन क्वीन' रेल सेवा शुरू हुई थी, जो ग्रेट इंडियन पेनिनसूला (जीआईपी) रेलवे की प्रमुख ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इस क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण शहरों में सेवा प्रदान करने के लिए यह पहली डीलक्स रेलगाड़ी शुरू की गई थी और 'दक्खन की रानी' के तौर पर प्रसिद्ध पुणे शहर के नाम पर इसका नाम रखा गया था। शुरू में रेलगाड़ी में 7 डिब्बों के दो रैक थे। प्रत्येक को लाल रंग के सजावटी सांचों में सिल्वर रंग और अन्य पर नीले रंग के सांचों में सुनहरे रंग की रेखा उकेरी गई थी। डिब्बों के मूल रैक की नीचे की फ्रेम का निर्माण इंग्लैंड में, जबकि डिब्बों का ढांचा जीआईपी रेलवे के माटुंगा कारखाने में निर्मित किया गया था।

क्या है

1. शुरूआत में 'डेक्कन क्वीन' में केवल प्रथम और द्वितीय श्रेणी थी। प्रथम श्रेणी को 01 जनवरी, 1949 को बंद कर दिया गया और द्वितीय श्रेणी की डिजाइन दोबारा तैयार कर इसे प्रथम श्रेणी में परिवर्तित किया गया। इसके बाद जून 1955 में इस रेल गाड़ी में पहली बार तृतीय श्रेणी उपलब्ध करायी गई। इसे अप्रैल, 1974 से द्वितीय श्रेणी के तौर पर दोबारा डिजाइन किया गया था।
2. 1966 में मूल रैकों के डिब्बों के स्थान पर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, पैरांबुर द्वारा निर्मित टेलीस्कोप रोधी स्टील के ढांचे वाले डिब्बे लगाए गए। इन डिब्बों में अधिक आराम के लिए इसकी डिजाइन और आंतरिक साज-सज्जा में सुधार किए गए। रैक में डिब्बों की संख्या भी 7 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। वर्तमान में इसमें अब 17 डिब्बे हैं।
3. इसकी शुरूआत से यात्रियों को उच्च स्तर का आराम प्रदान करने के अलावा रेलगाड़ी में कई सुधार किये गए। इनमें देश में पहली बार रोलर बियरिंग के डिब्बों की शुरूआत, विद्युत पैदा करने वाले डिब्बों के स्थान पर 110 वोल्ट प्रणाली के विद्युत उत्पादित करने वाले डिब्बे लगाना, यात्रियों के लिये अधिक स्थान उपलब्ध कराने हेतु पहली और द्वितीय श्रेणी की चेर कार की शुरूआत शामिल है।
4. हाल ही में इस रेलगाड़ी की रंग योजना में क्रीम और नीले रंग का इस्तेमाल कर इसके ऊपर लाल रंग की पट्टी बनाई गई है।
5. बेहतर सुविधाओं, आराम के स्तर में सुधार और बेहतर गुणवत्ता की सेवा प्राप्त करने की यात्रियों की अपेक्षाओं के चलते डेक्कन क्वीन में संपूर्ण परिवर्तन करना आवश्यक समझा गया।

6. अंतर्राष्ट्रीय सेवा कंपनी द्वारा डेक्कन क्वीन की प्रबंधन प्रणाली (2123डीएन/2124अप) का आकलन किया गया और यह नवंबर, 2003 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के संयुक्त मान्यता प्रणाली के अंतर्गत आईएसओ 9001:2000 के सभी मानदंडों पर खरी उतरी थी।
7. वर्तमान में डेक्कन क्वीन (12123/12124) में 17 डिब्बे हैं, जिनमें 4 एसी चेरर कार, 01 बूफे कार, 10 द्वितीय श्रेणी की चेरर कार और द्वितीय श्रेणी सह ब्रेक वैन शामिल हैं।

सिसी फिर बने मिस्र के राष्ट्रपति

मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सिसी ने राष्ट्रपति के रूप में चार साल के अपने दूसरे कार्यकाल के लिए 2 जून 2018 को शपथ ली। सिसी ने गत मार्च में हुए राष्ट्रपति चुनाव में वैध वोटों में से 97 प्रतिशत वोट हासिल किए थे। उन्होंने सदन में अपनी सरकार के सदस्यों के सामने शपथ ली।

क्या है

1. शपथ ग्रहण के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई। अल सिसी ने अपने संबोधन में स्थिरता बहाली, अर्थव्यवस्था में सुधार करने और उत्तरी सिनाई प्रायद्वीप में आतंकवाद से मुकाबले पर काम करने की प्रतिबद्धता जताई।
2. सिसी ने 2014 में भारी बहुमत से जीत दर्ज की थी। सिसी के सामने चुनाव में कोई गंभीर चुनौती नहीं थी। उनके एकमात्र प्रतिद्वंद्वी मूसा मुस्तफा मूसा अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय थे। मूसा स्वयं भी सिसी समर्थक रहे हैं।

आत्महत्या की कोशिश अब अपराध नहीं

भारत में आत्महत्या करने के लिए प्रयास करना अब अपराध नहीं रहा। मानसिक रूप से बीमार बच्चों को इलाज के लिए अब बिजली के झटके नहीं दिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के तहत आत्महत्या की कोशिश करने वाला व्यक्ति अपराधी माना जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसके लिए तनाव की अधिकता समेत पर्याप्त कारण बताने होंगे। अगर उसने किसी को फंसाने के लिए आत्महत्या की कोशिश की होगी, तो उस पर संशोधित अधिनियम में अलग प्रावधान हैं।

क्या है

1. नए प्रावधान के अनुसार सरकार पीड़ित व्यक्ति की देखभाल करेगी, उसका इलाज कराएगी और उसके पुनर्वास का बंदोबस्त करेगी। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए पूरी कवायद मुफ्त होगी।
2. माना जाएगा कि तनाव की अधिकता या मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के चलते व्यक्ति ने आत्महत्या की कोशिश की। स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना इस कृत्य को मानवाधिकारों से जोड़ने की पहल मानी जा रही है। आत्महत्या के प्रयास को अपराध से हटाकर मानसिक बीमारी के तौर पर स्वीकार किया गया है।
3. इसके अतिरिक्त अधिनियम में मानसिक बीमार बच्चों को इलेक्ट्रिक शॉक (बिजली के झटके) देकर इलाज करना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।
4. व्यस्कों को भी अब बेहोश करने और मांसपेशियों को राहत देने वाली दवा देने के बाद ही बिजली का झटका दिया जा सकेगा। साथ ही मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को जंजीर से जकड़े जाने पर भी रोक लगा दी गई है।
5. कहा गया है कि सभी को सम्मान से जीने का अधिकार है, भले ही वह मानसिक रूप से बीमार ही क्यों न हो। इलाज के नाम पर मानसिक रूप से बीमार स्त्री या पुरुष का अब बंध्याकरण भी नहीं किया जा सकेगा। नई व्यवस्था में किसी भी आधार पर भेद नहीं किया जा सकेगा।

6. सभी जाति, धर्म, लिंग के लोगों पर ये नियम लागू होंगे। मानसिक रूप से बीमार लोगों के कल्याण के लिए सरकार ने और भी कई प्रावधान किए हैं जिससे उनकी बेतरतीब जिंदगी में सुधार लाया जा सके।

कनाडा ने विश्व व्यापार संगठन में की शिकायत

आयातित स्टील व एल्यूमिनियम उत्पादों पर संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) की ओर से आयात शुल्क लगाने के फैसले के खिलाफ कनाडा ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में शिकायत दर्ज कराई है। कनाडा की विदेश मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने एक बयान में कहा कि अमेरिका ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा अक्षुण्ण रखने के झूठे बहाने पर ये एकतरफा शुल्क लगाए हैं। यह डब्ल्यूटीओ में अमेरिका द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं के खिलाफ है।

क्या है

1. डब्ल्यूटीओ में अमेरिका के खिलाफ गई इस शिकायत में वह यूरोपीय संघ (ईयू) से भी सहयोग करेगा। ईयू ने भी अमेरिका के इस फैसले को डब्ल्यूटीओ में चुनौती दी है।
2. कनाडा ने नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (नाफ्टा) के अध्याय-20 के कारोबारी विवाद तंत्र के तहत अमेरिका द्वारा उठाए कदमों की समीक्षा का भी आग्रह किया।
3. फ्रीलैंड का कहना था कि कनाडा नॉर्थ अमेरिकन एयरोस्पेस डिफेंस कमांड (नोराड) और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन (नाटो) के तहत अमेरिका का प्रमुख सहयोगी देश है।
4. वह अमेरिकी स्टील का सबसे बड़ा आयातक भी है। ऐसे में कनाडा से आयातित स्टील और एल्यूमिनियम पर अमेरिका द्वारा शुल्क लगाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। गौरतलब है कि बीते गुरुवार को अमेरिका ने कनाडा, मैक्सिको और ईयू को स्टील व एल्यूमिनियम पर लगाए अपने आयात शुल्क पर छूट के दायरे से बाहर कर दिया था।
5. इस बीच, यूरोपीय संघ ने अमेरिका के स्टील व एल्यूमिनियम उत्पाद पर आयात शुल्क के खिलाफ पहली बार प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई करते हुए अमेरिकी उत्पादों पर भी आयात शुल्क लगा दिया है।
6. ट्रंप ने की नाफ्टा के दो-फाइ की वकालत: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाफ्टा को दो अलग-अलग कारोबारी हिस्सों में बांटने की वकालत की है। ट्रंप का मानना है कि कनाडा के साथ अमेरिका के कारोबारी रिश्तों की शर्तें एक हिस्से के तहत, जबकि मैक्सिको के साथ कारोबारी रिश्तों की शर्तें दूसरे हिस्से के तहत होनी चाहिए।

राष्ट्रपति भवन में गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों की दो दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाला यह 49वां गवर्नर्स कांफ्रेंस है और राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में ये दूसरा सम्मेलन होगा। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में राज्यपाल सम्मेलन में शामिल होने पहुंच चुके हैं।

क्या है

1. राज्यपालों का पहला सम्मेलन राष्ट्रपति भवन में 1949 में शुरू हुआ था। उस दौरान भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल सी. राजगोपालाचारी की अध्यक्षता में ये सम्मेलन कराया गया था। 4 जून 2018 से शुरू हो रहे दो दिवसीय सम्मेलन में पांच अलग-अलग सत्रों के दौरान महत्वपूर्ण विषयगत मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
2. सम्मेलन का दूसरा सत्र में भारत सरकार और आंतरिक सुरक्षा विभाग के द्वारा संचालित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के बारे में बताया जाएगा। इस सत्र के दौरान नीति आयोग के सीईओ, वाइस चेरमैन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के द्वारा प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे।

3. तीसरे सत्र में राज्य विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए कौशल विकास की जरूरत पर चर्चा की जाएगी। गुजरात के राज्यपाल इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे। इस सत्र के दौरान इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन विभाग के उच्च शिक्षा सचिव अपना प्रजेंटेशन देंगे।
4. चौथे सत्र में राज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर राज्यपाल-विकास के राजदूत: समाजिक बदलाव के लिए अहम भूमिका निभाने वाले एजेंट नामक रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि ये रिपोर्ट राज्यपाल समिति के द्वारा 9 जनवरी 2018 को राष्ट्रपति को सौंपा गया था। राज्यपाल समिति का गठन अक्टूबर 2017 में 48वें राज्यपाल सम्मेलन में किया गया था। इस चौथे सत्र को आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के राज्यपाल संबोधित करेंगे।
5. 5 जून 2018 को कार्यक्रम का पांचवा सत्र आयोजित होगा जिसमें इस पर चर्चा की जाएगी कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को किन तरीकों से मनाया जाएगा। इस सत्र में ग्राम स्वराज अभियान और स्वच्छता इंटर्नशिप पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, इसके बाद राज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर इस पर अपनी सलाह भी देंगे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे।
6. छठे और अंतिम सत्र में पिछले सत्रों के आयोजन पर चर्चा और विमर्श किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडु, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस अंतिम सत्र का हिस्सा होंगे।
7. केंद्र शासित प्रदेशों पर एक विशेष सत्र 5 जून, 2018 को आयोजित किया जाएगा, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर/प्रशासक विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा करेंगे। कैबिनेट सचिव, गृह सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक का हिस्सा होंगे।
8. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर सम्मेलन में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति; प्रधान मंत्री; गृह मामलों के केंद्रीय मंत्री; विदेशी मामले; मानव संसाधन विकास; कौशल विकास और उद्यमिता; एनआईटीआई आयोग के संस्कृति और उपाध्यक्ष और सीईओ मंत्रालय और विभिन्न मंत्रालयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के राज्य मंत्री (आई/सी) भी भाग लेंगे।

तूतीकोरिन मामले में त्वरित सुनवाई से SC का इंकार

तूतीकोरिन या तूतुकुडी में स्टरलाइट विरोधी प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में मारे गए लोगों के परिवारों द्वारा दर्ज याचिका में तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून 2018 को इंकार कर दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए तारीख निश्चित नहीं की और कहा कि गर्मियों के अवकाश के बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। तूतीकोरिन में गत 22 व 23 मई को हुई हिंसा के दौरान 13 लोग मारे गए थे।

क्या है

1. बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने स्टरलाइट प्लांट को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि वेदांता ग्रुप के कॉपर प्लांट को हमेशा के लिए सील कर दिया जाए।
2. यह कार्रवाई 1974 के वाटर एक्ट के तहत की गई है। सरकार का कहना है कि अनुच्छेद 48-ए के तहत उसे ऐसा करने का अधिकार है।
3. राज्य मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने कहा कि राज्य की जनता के भावना का सम्मान करते हुए यह फैसला लिया गया। यह प्लांट भारत का दूसरा सबसे बड़ा कॉपर बनाने वाला प्लांट है। इसकी क्षमता सालाना 400000 टन उत्पादन है।
4. तूतीकोरिन के निवासियों ने स्टरलाइट पर दोहरे आरोप लगाए हैं। पहला आरोप है कि कंपनी इलाके में प्रदूषण फैला रही है। 2008 में तिरुनेलवेल्ली मेडिकल कॉलेज ने सेहत पर एक अध्ययन किया। जिससे पता चला कि स्टरलाइट

- प्लांट के आस-पास के इलाके में लोगों को सांस, कान, नाक, गले की बीमारियां हो रही थीं और स्थानीय महिलाओं को भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। पानी में लोहे की मात्रा कुछ ज्यादा ही पाई गई थी।
5. स्थानीय लोगों का दूसरा आरोप 2009 में केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय की तरफ से कंपनी को दिया गया पर्यावरण का क्लीयरेंस को लेकर है। साथ ही तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2016 में कंपनी को अपनी स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टर (यूनिट 2) के विस्तार के लिए निर्माण कार्य की इजाजत देने को लेकर भी सवाल उठे हैं।

देश का सबसे बड़ा मिलिट्री अभियान

आज (5 जून 2018) से 34 साल पहले वर्ष 1984 में दो घटनाओं की टीस आज भी लोगों के जेहन में है। उस साल जून और अक्टूबर के महीने में ऐसी घटनाएं हुई जिससे देश स्तब्ध था। पंजाब में आतंकवाद अपने पांव पसार रहा था और उसकी अगुवाई करने का आरोप भिंडरावाले पर लगा। तत्कालीन कांग्रेस ने एक ऐसा फैसला किया जिसका भयावह अंत 31 अक्टूबर 1984 को हुआ। एक तरफ 3 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लूस्टार में भिंडरावाला मारा गया और ठीक उसके पांच महीने बाद अक्टूबर 1984 में ही इंदिरा गांधी अपने ही सुरक्षा दस्ते का ही शिकार हो गयीं। तीन दिन तक चली कार्रवाई में स्वर्ण मंदिर में 492 लोगों की जान चली गयी थी। इसके अलावा सेना के चार अधिकारियों समेत 83 जवान शहीद हो गए थे। ऑपरेशन ब्लूस्टार की समाप्ति के बाद तत्कालीन रक्षा राज्यमंत्री के पी सिंह देव चाहते थे कि ये जानकारी पीएम इंदिरा गांधी तक पहुंचायी जाए। इंदिरा गांधी को जब उनके सचिव आर के धवन ने जानकारी दी तो उनका पहली प्रतिक्रिया ये थी कि, हे भगवान ये क्या हुआ उन लोगों ने बताया था कि इतनी मौतें नहीं होंगी। दरअसल ऑपरेशन ब्लूस्टार से पहले तत्कालीन सेना अध्यक्ष अरुण कुमार वैद्य ने बताया कि ऑपरेशन को शांतिपूर्ण ढंग से अंजाम दिया जाएगा।

क्यों हुआ ऑपरेशन ब्लूस्टार?

1. 1983 में पंजाब पुलिस के डीआईजी एएस अटवाल ही हत्या से माहौल गर्मा गया। उसी साल जालंधर के पास बंदूकधारियों ने पंजाब रोडवेज की बस में चुन-चुनकर हिंदुओं की हत्या कर दी। इसके बाद विमान हाईजैक हुए।
2. स्थिति काबू से बाहर हो गई और केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। अब तक स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना चुका भिंडरावाला सरकार के निशाने पर आ चुका था और स्वर्ण मंदिर को चरमपंथियों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन ब्लूस्टार प्लान किया गया।

क्या हुआ खालिस्तान का?

1. 1990 के दशक में खालिस्तान की मांग कमजोर पड़ती गई। हालांकि ऑपरेशन ब्लू स्टार की तारीख पर आज भी हर साल पंजाब में विरोध प्रदर्शन होता है।
2. ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका में रह रहे सिख समुदायों में अभी भी अलग खलिस्तान को लेकर मांग उठती रही है। समझा जाता है कि भारत से बाहर दो से तीन करोड़ सिख रहे हैं। उनमें से ज्यादातर का भारतीय पंजाब में कोई न कोई जुड़ाव है।

बाल संरक्षण पर राष्ट्रीय परामर्श सम्मेलन का आयोजन

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में बाल संरक्षण पर राष्ट्रीय परामर्श सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा यौन अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम (पाँक्सो), 2012 पर चर्चा की गई। विचार-विमर्श में विभिन्न राज्यों के पुलिस विभाग द्वारा श्रेष्ठ व्यवहारों और अनुभवों को साझा किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्यों के महिला और बाल विकास विभागों, राज्य पुलिस विभागों, गृह मंत्रालय तथा एनसीपीसीआर के साथ बाल संरक्षण तथा बाल कल्याण से संबंधित विषयों पर

विचार-विमर्श की पहल की है। राष्ट्रीय सम्मेलन के पहले भाग में किशोर न्याय अधिनियम, 2015 तथा पॉक्सो अधिनियम, 2012, ट्रैक चाइल्ड, चाइल्डलाइन (1098) से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई।

क्या है

1. राष्ट्रीय परामर्श के दूसरे भाग में सीपीएस योजना के बाल देखभाल और संरक्षण पर फोकस किया गया और राज्यों में क्रियान्वयन के क्षेत्रों की पहचान की गई और इसके समाधान के प्रस्ताव पेश किए गए।
2. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय, बाल (देखभाल तथा संरक्षण) अधिनियम, 2015, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो) अधिनियम और बाल संरक्षण सेवाओं के विभिन्न कानूनों का (सीपीएस) को आईसीडीएस के अंतर्गत लागू कर रहा है ताकि बच्चों की दुर्व्यवहारों से सुरक्षा की जा सके और उनके हितों को सुनिश्चित किया जा सके।
3. किशोर न्याय अधिनियम, 2015 राज्यों को बच्चों की देखभाल और संरक्षण तथा कानून की चपेट में आए बच्चों को सुरक्षा कवच प्रदान करने का अधिकार देता है।
4. यह अधिनियम इन बच्चों की संस्थागत और गैर-संस्थागत देखभाल का प्रावधान कुछ निश्चित वैधानिक सेवाओं के साथ करता है। यह अधिनियम लैंगिक रूप से तटस्थ है और 18 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को बालक/बालिका मानता है।
5. आईसीडीएस के अंतर्गत 24&7 चाइल्ड हेल्पलाइन की व्यवस्था है और खोए हुए बच्चों का पता लाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल है। इस योजना के अंतर्गत 1508 सीसीआई को औसतन 50 बच्चों के साथ समर्थन दिया जा रहा है।
6. चाइल्ड लाइन का विस्तार 437 स्थानों तक किया गया है और 60 प्रमुख स्टेशनों पर रेलवे चाइल्ड लाइन कार्य कर रहा है। खोए हुए बच्चों को परिवार से मिलाने में ट्रैक चाइल्ड पोर्टल तथा खोयापाया ऐप काफी सफल हुए हैं।

QS वर्ल्ड रैंकिंग सूची 2019

आईआईटी बॉम्बे, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी दिल्ली को QS वर्ल्ड रैंकिंग सूची 2019 में टॉप 200 में शामिल किया गया है। 6 जून 2018 को जारी हुई प्रतिष्ठित QS वर्ल्ड रैंकिंग लिस्ट में टॉप 1000 यूनिवर्सिटी में भारतीय यूनिवर्सिटी की संख्या 20 से बढ़कर 24 हो गई है।

क्या है

1. आईआईटी बॉम्बे को भारत का टॉप संस्थान करार दिया गया है। आईआईटी बॉम्बे 2018 में 162वें स्थान पर रखा गया था। लेकिन 2019 रैंकिंग में इसकी स्थिति 17 पायदान बेहतर हुई है।
2. इसने आईआईटी दिल्ली को पीछे छोड़ा है। आईआईटी दिल्ली 172वें स्थान पर कायम है। आईआईएससी ने भी आईआईटी दिल्ली को पछाड़ते हुए 170वां स्थान हासिल किया है।
3. वैश्विक तौर पर देखें तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहले स्थान पर कायम है। लगातार 7 सालों से वह नंबर 1 है। QS रैंकिंग में हर वर्ष 85 देशों की टॉप 1000 यूनिवर्सिटी को जगह दी जाती है। 2019 की रैंकिंग में भारत की पांच आईआईटी और आईआईएससी को टॉप 500 में जगह दी गई है।
4. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दूसरे और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पर है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चौथे और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड पांचवें स्थान पर है।
5. हालांकि कैंब्रिज यूनिवर्सिटी पांचवें से छठें स्थान पर पहुंच गयी है। एशिया में सिंगापुर की दो यूनिवर्सिटी टॉप 20 में शामिल है।

कुडानकुलम के लिए सुरक्षित ईंधन की आपूर्ति करेगा रूस

रूसी नेशनल एटॉमिक पावर कॉरपोरेशन 'रॉसएटम' के तकनीकी सहयोग से कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट (केएनपीपी) के दो चालू रिएक्टरों में नया अत्याधुनिक और सुरक्षित ईंधन भरा जाएगा। 'रॉसएटम' की ईंधन इकाई टीवीईएल के वाइस प्रेसीडेंट (अनुसंधान एवं विकास) अलेक्जेंडर उग्रीयूमाव ने बताया कि उनकी कंपनी के सहयोग से तमिलनाडु में निर्माणाधीन दो अन्य इकाइयों में भी यही ईंधन भरा जाएगा।

क्या है

1. उन्होंने उम्मीद जताई कि केएनपीपी में नए ईंधन की आपूर्ति के लिए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआइएल) और उनकी कंपनी के बीच समझौते को जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
2. मालूम हो कि केएनपीपी की वर्तमान एक हजार मेगावाट की प्रत्येक इकाई के लिए 'रॉसएटम' ही उपकरण आपूर्तिकर्ता भी है।

मिताली राज का अनोखा रिकॉर्ड

दुनिया की बेस्ट महिला क्रिकेटर्स में शुमार भारत की मिताली राज ने अपने नाम वो रिकॉर्ड कर डाला है, जो चाहकर भी कोई पुरुष क्रिकेटर नहीं तोड़ पाएगा। महिला एशिया कप ट्वेंटी20 टूर्नामेंट में 7 जून 2018 को उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 23 रनों की पारी खेली और इस दौरान ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर डाला, जो अब कोई नहीं तोड़ पाएगा। 33 गेंद पर 23 रनों की पारी के दौरान मिताली राज ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2000 रनों का आंकड़ा छू लिया। ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं।

क्या है

1. मिताली से पहले ये कारनामा कोई पुरुष क्रिकेटर भी नहीं कर सका है। इस तरह से सबसे पहले 2000 टी20 इंटरनेशनल रनों का आंकड़ा छूने वाली मिताली हमेशा पहली भारतीय रहेंगी।
2. मिताली के नाम 74 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 38.01 की औसत से 2015 रन दर्ज हो गए हैं। मिताली के नाम इस दौरान 14 हाफसेंचुरी दर्ज हैं और 18 बार वो नॉटआउट रही हैं।
3. मिताली के बाद भारत की ओर से दूसरे नंबर पर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली हैं। विराट के नाम 57 मैचों में 1983 रन ही दर्ज हैं।
4. इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर 1852 रनों के साथ रोहित शर्मा और चौथे नंबर पर 1499 रनों के साथ सुरेश रैना हैं। पांचवें नंबर पर हरमनप्रीत कौर हैं, जिन्होंने 79 मैचों में 1467 रन बनाए हैं।
5. भारत ने श्रीलंका को सात विकेट से हराया। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 107 रन बनाए, जवाब में भारत ने 18.5 ओवर में तीन विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। वेदा कृष्णमूर्ति ने चौका जड़कर भारत को जीत दिलाई।

ऑशियन स्टडी में शामिल हुए 20 अमेरिकी वैज्ञानिक

विशाल हिंद महासागर पर अध्ययन करने के लिए 20 अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक टीम मुख्य अनुसंधान पोत रोनाल्ड एच ब्राउन के साथ गोवा के समुद्र तट पर पहुंच गई। भारतीय और अमेरिकी वैज्ञानिक सागर और वायुमंडलीय निगरानी के क्षेत्र में सहयोग के एक दशक पूरा होने पर गोवा में मिल रहे हैं। भारत और आसपास के अन्य देशों सहित अमेरिका तक इस महासागर के वायुमंडलीय घटनाक्रम का काफी प्रभाव देखने को मिलता है।

क्या है

1. यूएस वाणिज्य दूतावास के जनरल एडगार्ड कागन ने इस मौके पर कहा, अमेरिका और भारतीय वैज्ञानिकों के इस सहयोग को देखकर हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। यह साथ काम करने की हमारी क्षमता का दर्शाता है। यह दिखाता है कि दोनों देश साथ मिलकर कैसे मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हैं।

2. भारत के शीर्ष सागर, वायुमंडल और मत्स्य विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत वैज्ञानिकों से अमेरिका के नेशनल ओशनिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (एनओए) के 20 वैज्ञानिकों की बैठक जल्द ही होगी। इस दौरान वे इस क्षेत्र में सहयोग की स्थिति की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्रवाई के बाबत निर्णय करेंगे।
3. एनओए के सहायक प्रशासक (महासागर और वायुमंडलीय अनुसंधान) और एनओए के प्रमुख कार्यवाहक वैज्ञानिक ब्रेग मैकलीन ने कहा कि पश्चिमी उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर में होने वाले मैडेन जूलियन ऑसीलेशन का अमेरिका के मौसम पर सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। मैकलीन इस बैठक में अमेरिका के उच्चाधिकार प्राप्त प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।
4. अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने बताया कि ये अध्ययन दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करेगा। इस अध्ययन में जो डाटा एकत्रित किया जाएगा, उसका उपयोग मिलकर किया जाएगा।

बेंगलुरु दूसरा सबसे सस्ता शहर

शहर बदलने के मामले में पहले महीने के रहन-सहन खर्च के आधार पर बेंगलुरु विश्व का दूसरा सबसे सस्ता शहर है। मिस्र की राजधानी काहिरा सबसे सस्ता शहर बनकर उभरा है। तैयार अपार्टमेंट खोजने की सुविधा देने वाली कंपनी नेस्टपिक के एक अध्ययन के अनुसार, काहिरा में पहले महीने का जीवन यापन खर्च 656 डॉलर है जबकि बेंगलुरु में यह 742.13 डॉलर है।

क्या है

1. शहर बदलने के पहले महीने के जीवनयापन खर्च के मामले में अन्य सस्ते शहरों में बुखारेस्ट (754.83 डॉलर), बुडापेस्ट (870.58 डॉलर), रिगा (931.56 डॉलर) और मैक्सिको सिटी (943.15 डॉलर) शामिल हैं। दुबई इस सूची में सबसे महंगा शहर बनकर उभरा है। दुबई का पहले महीने का जीवनयापन खर्च 4,251.68 डॉलर आया है। इसके बाद ऑकलैंड (4002.76 डॉलर) और सैन फ्रांसिस्को (3,768.68 डॉलर) का स्थान है।
2. रिपोर्ट के अनुसार यह खर्च न्यूयॉर्क में 3,374.21 डॉलर, लंदन में 3,207.41 डॉलर, सिडनी में 3,000.27 डॉलर, ओस्लो में 2,921.90 डॉलर और ज्यूरिख में 2,899.98 डॉलर है।
3. सर्वेक्षण के अनुसार खान-पान के मामले में स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख 1,193.96 डॉलर के साथ सबसे महंगा और बेंगलुरु 255.97 डॉलर के साथ सबसे सस्ता शहर है।
4. इसी तरह परिवहन के मामले में लंदन 168.71 डॉलर के साथ सबसे महंगा और काहिरा 7.14 डॉलर के साथ सबसे सस्ता शहर है।

भारत को मिलेंगे 6 अपाचे हेलीकॉप्टर

अमेरिकी सरकार ने भारत को छह अपाचे जंगी हेलीकॉप्टर बेचने के सौदे को मंजूरी दे दी है। ये सौदा 6340 करोड़ रुपये (930 मिलियन डॉलर) में किया गया है। इस समझौते को अमेरिकी कांग्रेस के पास भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि अगर इस समझौते पर कोई भी सांसद सवाल नहीं उठाता है तो इसे मंजूरी के लिए आगे भेज दिया जाएगा। बोइंग और भारतीय साझेदार टाटा ने भारत में अपाचे हेलीकॉप्टर की बाँडी बनानी शुरू कर दी है, लेकिन 12 जून 2018 को जिस सौदे को मंजूरी दी गई है उसके तहत भारत को पूरी तरह तैयार हेलीकॉप्टर बेचा जाएगा। बता दें इन हेलीकॉप्टर्स को अमेरिकी कंपनी बोइंग बनाती है और इन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है।

क्या है

1. हेलीकॉप्टर के अलावा, समझौते में नाइट विजन सेंसर, जीपीएस मार्गदर्शन, एंटी-कवच और स्टिंगर एयर-टू-एयर मिसाइल शामिल हैं। अमेरिकी रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने एक बयान में कहा, "AH-64E हर तरह के खतरों का सामना करने और अपनी सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए भारत की रक्षात्मक क्षमता में वृद्धि प्रदान करेगा।

2. अपाचे को यूएस आर्मी के एडवांस्ड अटैक हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के लिए डेवलप किया गया था। इसने पहली उड़ान 30 सितंबर 1975 को भरी थी। अप्रैल 1986 में अपाचे को यूएस आर्मी में शामिल किया गया था। हालांकि, तब ये इतने मॉडर्न नहीं थे, जितने आज हैं।
3. फिलहाल, अपाचे को दुनिया का सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है। आज ये हेलीकॉप्टर यूएस आर्मी के अलावा इजरायल, मिस्र और नीदरलैंड की आर्मी भी इस्तेमाल करती है।
4. भारत एवं अमेरिका के बीच द्विपक्षीय रक्षा कारोबार वर्ष 2008 से करीब शून्य से 15 अरब डॉलर तक बढ़ा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, अगले दशक तक सैन्य आधुनिकीकरण पर भारत के अरबों खर्च करने की संभावना है और हम अमेरिकी उद्योग जगत के लिये यह मौका हासिल करने को इच्छुक हैं। ऐसी बिक्रियों से ना सिर्फ हमारे रक्षा सहयोग को समर्थन मिलेगा बल्कि इनसे देश के अंदर नौकरियां भी पैदा होंगी।
5. हाल के वर्षों में अमेरिका ने सरकारी स्तर पर भारत को सी-17 परिवहन विमान, 155 मिमी लाइट-वेट टोड होवित्जर, यूजीएम-84 एल हारपून मिसाइल, सपोर्ट फॉर सी-130जे सुपर हरक्युलिस विमान और रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल एवं परमाणु (सीबीआरएन) सहयोग उपकरण बेचे हैं।

हैल्पएज इंडिया रिपोर्ट

एक नए सर्वे के मुताबिक दिल्ली, भारत के ऐसे पांच शहरों में से एक है, जहां बुजुर्गों के साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार होता है। हैल्पएज इंडिया ने 23 शहरों की एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक बुजुर्गों के साथ सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार मैंगलोर (47 फीसदी), उसके बाद अहमदाबाद (46 फीसदी), भोपाल (39 फीसदी) अमृतसर (35 फीसदी) और दिल्ली (33 फीसदी) में होता है।

क्या है

1. इस शोध का उद्देश्य यह पता लगाना था कि दुर्व्यवहार किस हद तक, कितना ज्यादा, किस रूप में, कितनी बार होता है और इसके पीछे कारण क्या हैं।
2. इसमें पता चला कि लगभग एक चौथाई बुजुर्ग आबादी व्यक्तिगत तौर पर उत्पीड़न का सामना करती हैं, और उनका उत्पीड़न करने वालों में ज्यादातर या तो उनके बेटे (52 फीसदी) होते हैं या फिर उनकी बहुएं (34 फीसदी)।
3. हैल्पएज इंडिया के सीईओ मैथ्यू चेरियन ने कहा, दुर्भाग्य से बुजुर्गों का उत्पीड़न घर से शुरू होता है और इसे अंजाम वे लोग देते हैं जिन पर वह सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं।
4. उन्होंने बताया, “इस वर्ष, दुर्व्यवहार को अंजाम देने वाले लोगों में सबसे पहले बेटे हैं, उसके बाद बहुएं हैं। पहले के सर्वेक्षणों में पाया गया कि बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों में सबसे आगे बहुएं होती हैं।
5. इसमें यह भी पता चला कि दुर्व्यवहार के शिकार 82 फीसदी बुजुर्ग परिवार की खातिर इसकी शिकायत नहीं करते या वह यह नहीं जानते कि समस्या से किस प्रकार निपटा जा सकता है।